The Public Hub

पेज 6 | स्पोर्ट्स

वर्ष 1 अंक : 4 ₹ 4.00 पृष्ठ-8

www.thepublichub.in

जयपुर
बुधवार 25 फरवरी, 2026

डीसीपी ट्रैफिक की चेतावनी : सात दिन में पार्किंग... | 3

The Public Hub Exclusive Report : CBSE की आड़ में बड़ा खेल

प्रदेश के 25,000 निजी स्कूलों के पास नहीं है राज्य की मान्यता, कागजों में सिमटा शिक्षा विभाग

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में मान्यताओं और नियमों के पालन को लेकर एक गंभीर प्रशासनिक विषय सामने आया है। प्रदेश के लगभग 25 हजार निजी स्कूलों द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के संचालन में राज्य सरकार के निर्धारित मापदंडों की कथित अनदेखी की जा रही है। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्धता तो रखते हैं, लेकिन राज्य शिक्षा विभाग से आवश्यक क्रमोन्नति (Recognition) की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण तकनीकी रूप से सवालों के घेरे में हैं।

नियमों की प्रक्रिया में अंतराल : *शिक्षा विभाग के नियमानुसार, किसी भी बोर्ड से संबद्धता लेने से पूर्व संबंधित कक्षा स्तर के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र और क्रमोन्नति लेना अनिवार्य है। विभागीय आदेश (दिनांक 22.12.2022) के अनुसार, यदि किसी विद्यालय के पास*

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

राज्य की मान्यता नहीं है, तो वह उच्च कक्षाओं का संचालन नहीं कर सकता। वर्तमान में स्थिति यह है कि कई स्कूल केवल कक्षा 1 से 8 तक की राज्य मान्यता पर चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हजारों स्कूल केवल कक्षा 1 से 8 तक की राज्य मान्यता पर कक्षा 12 तक की पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूल प्रबंधन केवल सीबीएसई की संबद्धता को ही पर्याप्त मान रहे हैं, जो कि राजस्थान गैर-सरकारी संस्था अधिनियम 1989 का सीधा उल्लंघन है।

निगरानी में चूक और राजस्व का घाटा : *इस तकनीकी खामी के कारण सरकार के सामने इनकी नियमित मॉनिटरिंग और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये स्कूल PSP पोर्टल पर उच्च माध्यमिक स्तर पर पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए सरकार के पास इन छात्रों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इससे छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं की जांच करना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर मान्यता और क्रमोन्नति शुल्क के रूप में राज्य सरकार को मिलने वाले करोड़ों रुपये के राजस्व का हर साल नुकसान हो रहा है।*

अमायरा केस : सरकारी तंत्र की लाचारी आई सामने

हाल ही में जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की आत्महत्या के मामले ने इस फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। जब CBSE ने स्कूल की संबद्धता रद्द की, तो राज्य सरकार कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी क्योंकि तकनीकी रूप से वह स्कूल राज्य के उच्च माध्यमिक रिकॉर्ड में था ही नहीं। यदि स्कूल राज्य की मॉनिटरिंग में होता, तो विभाग पहले ही उस पर नकेल कस सकता था।

शिक्षा विभाग आदेशों की नहीं हो रही पालना: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकाने द्वारा 22 दिसम्बर, 2022 को जारी आदेश(क्रमांक 29) स्पष्ट है कि अन्य बोर्ड की संबद्धता से पहले राज्य से क्रमोन्नत लेना अनिवार्य है, लेकिन शिक्षा विभाग अपने की आदेशों की पालना नहीं करवा पा रहा है।

सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते निजी स्कूल वाले इन सरकारी आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसी कारण शिक्षा विभाग के ये आदेश कागजी खानापूर्ति बनकर रख गए हैं।

विधानसभा में गूंजा 'फर्जी डिग्री' का मुद्दा : 10 निजी विश्वविद्यालयों की हो रही जांच, अयोग्यों ने हथियाई सरकारी नौकरियां

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राजस्थान में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर बांटी जा रही फर्जी डिग्रियों का मामला विधानसभा में गर्माया रहा। इन डिग्रियों के आधार पर बड़ी संख्या में अयोग्य युवा सरकारी सेवा में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि फर्जी डिग्री के सहारे कितने लोग वर्तमान में सरकारी पदों पर नियुक्त हैं।

उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश में कुल 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं, जिनमें से शिकायतों के आधार पर 10 विश्वविद्यालयों के खिलाफ जांच की जा रही है।

इन विश्वविद्यालयों की जांच जारी

ओपीजेएस विवि (चूरू), सिंघानिया विवि (झुंझुनूं), सनराइज विवि (अलवर), श्रीधर विवि, (झुंझुनूं), मेवाड़ विवि, (चित्तौड़गढ़), माधव विवि, (सिरोही), रैफल्स विवि (अलवर), निर्वाण विवि (जयपुर), यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जयपुर), जगदीश झबरमल टिबड़ेवाला विवि (झुंझुनूं)। इस फर्जीवाड़े में अब तक कई प्रभावी नियुक्तियों और दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ओपीजेएस विवि (चूरू) मामला:

संचालक जोगेंद्र सिंह, पूर्व रजिस्ट्रार सरिता कड़वासरा, जितेंद्र यादव, संगीता कड़वासरा और सुमित सहित दलाल सुभाषचंद्र, प्रदीप शर्मा, परमजीत सिंह, गंगासिंह, अवनीश कंसल, अजय भारद्वाज, बाबूलाल पटेल तथा रवि त्यागी को गिरफ्तार किया गया है।

मेवाड़ विवि (चित्तौड़गढ़) मामला: तत्कालीन डीन (फार्मेसी) किशोर चंदुल, कार्यालय सहायक राजेश सिंह और उप परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा को जेल भेजा गया है।

विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सदन में कहा कि इस आपराधिक कृत्य में विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक, कार्मिकों और शिक्षकों की सीधी संलिप्तता है। फर्जी डिग्रियों के माध्यम से अयोग्य अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं, जिससे रात-दिन मेहनत करने वाले योग्य और वास्तविक अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने सरकार से इन फर्जी नियुक्तियों को चिह्नित करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

राजस्थान का 'फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम' बना देश में मिसाल

जयपुर (विसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जहाँ देश के अन्य राज्य अभी केवल एआई चैटबॉट्स के उपयोग तक ही सीमित हैं, वहीं राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने अत्याधुनिक 'फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम' को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। यह प्रणाली प्रदेश में शासन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित हो रही है।

1. **डमी कैंडिडेट्स पर प्रहार :** भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एक विशेष एआई-संचालित सिस्टम विकसित किया है।
   विशाल डेटाबेस : इस प्रणाली के तहत किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी के फोटो का मिलान 50 लाख रिकॉर्ड्स वाले विशाल डेटाबेस से किया जा सकता है।
   निष्पक्ष चयन : इस तकनीक के जरिए डमी कैंडिडेट्स को पकड़ना बेहद आसान हो गया है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हो रही है।

एआई से खुल रही अपराधियों की 'कुंडली'

2. **अपराधियों की पहचान हुई आसान :** अपराधियों और आदतन अपराधियों पर लगाम कसने के लिए राजस्थान सरकार ने एक प्रभावी एआई समाधान पेश किया है।
   10 लाख रिकॉर्ड्स : पुलिस प्रशासन अब संदिग्धों की फोटो का मिलान 10 लाख आपराधिक रिकॉर्ड्स से कर सकता है।
   तेजी से जांच : इस सिस्टम की मदद से पुराने अपराधियों की पहचान, उनके काम करने के तरीके (पैटर्न रिकग्निशन) और जांच प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आई है।
3. **लावारिस शवों की पहचान के लिए मानवीय पहल :** प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल अपराध रोकने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है।
   परिजनों तक पहुंच : अज्ञात या लावारिस शवों की पहचान के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है।
   गुमशुदा डेटाबेस : अज्ञात शवों के फोटो का मिलान गुमशुदा व्यक्तियों के डेटाबेस से किया जाता है, जिससे उनके परिजनों तक समय पर सूचना पहुँचाना संभव हो पा रहा है।

राजस्थान सरकार का यह 'फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम' न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुशासन की दिशा में तकनीकी नवाचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था तकनीकी छलांग और भ्रष्टाचार की दीमक के बीच संघर्ष

राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है, जहाँ एक ओर प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक तकनीक और समावेशन के नए प्रयोग हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 'फर्जी डिग्री' और 'पेपरलीक' जैसे संकटों ने इस पूरी प्रणाली की नींव को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार के हालिया रिपोर्ट कार्ड और विधानसभा में हुई तीखी बहसों ने प्रदेश की शैक्षणिक तस्वीर के दोनों पहलुओं को उजागर किया है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा समावेशन और नवाचार

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सरकार ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए 'राज पहल' कार्यक्रम के तहत एक साहसिक कदम उठाया है।

स्कूल ऑन व्हील्स : प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक 'चलता-फिरता स्कूल' शुरू किया जा रहा है, ताकि पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा बाधित न हो।

ब्रिज कोर्स और रेडिनेस कैम्प : पलायन के कारण पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा जोड़ने के लिए 6 महीने के 'स्कूल रेडिनेस कैम्प' और अस्थायी शिक्षा शिविरों की व्यवस्था की गई है।

डिजिटल सशक्तिकरण : सरकार ने पिछले दो वर्षों में 88,724 टैबलेट और लैपटॉप वितरित किए हैं, जो माध्यमिक स्तर के छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। हालांकि, इस क्षेत्र में चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। विधानसभा में हुई बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खोले गए कई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक पदों का सृजन नहीं किया गया, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नसीराबाद जैसे क्षेत्रों में विज्ञान संकाय (Science Faculty) की मांग और उस पर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए अभी भी ठोस धरातलीय कार्य की आवश्यकता है।

उच्च माध्यमिक एवं भर्ती परीक्षाएं एआई बनाम डमी कैंडिडेट

उच्च माध्यमिक स्तर के बाद युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकारी नौकरियों में पारदर्शी चयन की है। राजस्थान ने यहाँ 'फेस सिमिलैरिटी सर्च सिस्टम' (AI) को लागू कर देश के सामने एक मिसाल पेश की है।

भर्ती परीक्षाओं की शुचिता : 50 लाख रिकॉर्ड्स वाले विशाल डेटाबेस से फोटो मिलान के जरिए डमी कैंडिडेट्स को पकड़ना अब संभव हो गया है?

सफल आयोजन : सरकार का दावा है कि पिछले दो वर्षों में 351 परीक्षाएँ बिना किसी पेपरलीक के संपन्न कराई गई हैं, जो पिछले वर्षों के दागों को धोने का एक प्रयास है।

उच्च शिक्षा का काला सच : फर्जी डिग्रियों का व्यापार

शिक्षा व्यवस्था का सबसे विचलित करने वाला पहलू उच्च शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार है। विधानसभा में हुए खुलासे के अनुसार, राजस्थान के 53 में से 10 निजी विश्वविद्यालय वर्तमान में फर्जी डिग्रियों के मामले में जांच के घेरे में हैं।

अयोग्य अभ्यर्थियों का कब्जा : फर्जी डिग्रियों के आधार पर बड़ी संख्या में अयोग्य लोग सरकारी नौकरियों में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे योग्य और मेहनती युवाओं का हक मारा जा रहा है?

प्रशासनिक विफलता : ओपीजेएस (चूरू) और मेवाड़ विवि जैसे संस्थानों के संचालकों और अधिकारियों की गिरफ्तारियां यह दर्शाती हैं कि यह घोटाला केवल दलालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक और शिक्षक भी शामिल हैं?

- राखी सिंह, कार्यकारी संपादक

पीएचईडी में जल जीवन मिशन महाघोटाला | करोड़ों का फर्जी भुगतान-'सियासी' सन्नाटा

139 इंजीनियरों पर एसीबी की कब गिरेगी गाज?

जयपुर (विसं)। राजस्थान के जल जीवन मिशन (JJM) में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई ने महकमे में हड़कंप मचा रखा है। 17 फरवरी को ACB ने PHED के 9 अधिकारियों समेत 10 लोगों को सलाखों के पीछे भेजकर अपनी मंशा साफ कर दी थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उन 139 इंजीनियरों पर टिका है, जिन्होंने फील्ड में रहकर भ्रष्टाचार की इस 'पाइपलाइन' को कागज में बिछाकर उनका फर्जी भुगतान कर दिया था।

जानकारी के अनुसार मैसर्स श्याम ट्यूबवैल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन व मैसर्स गणपति ट्यूबवैल कंपनी के मालिक महेश मित्तल (दोनों आपस में जीजा-साले हैं) द्वारा न केवल फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 960 करोड़ के कार्य हासिल किए, बल्कि फील्ड में जलदाय विभाग

के इन 139 फील्ड इंजीनियर्स से मिलकर जल जीवन मिशन की इन योजनाओं के कार्य में बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों का फर्जी भुगतान भी उठाया गया था। जांच में सामने आया है कि मैसर्स श्याम ट्यूबवैल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन द्वारा सबसे पहले इरकॉन कंपनी के फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर जल जीवन मिशन में 25 करोड़ से कम राशि के करीब 2 दर्जन कार्य प्राप्त कर लिए। जब इतने बड़े फर्जीवाड़े के खेल पर जलदाय विभाग में किसी ने न तो सवाल उठाए और न ही कोई जांच की गई। इसके बाद पदमचंद जैन ने जल जीवन मिशन के बड़े कार्यों को हासिल करने के लिए अपने साले महेश मित्तल की फर्म गणपति ट्यूबवैल कंपनी के नाम से इनकॉन कंपनी के बड़े कार्यों के कूटरचित फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जलदाय विभाग में बड़े काम हासिल करने के साथ ही और भी नए कार्यों में टेंडर डाल दिए।

इन कार्यों को लेकर शिकायतें होने के बाद जब मामला खुलने लगा तो पदमचंद जैन द्वारा इस मामले के दबाने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को मोटा पैसा खिलाकर इस मामले का दबाने के साथ ही करोड़ों का फर्जी भुगतान उठा लिया और नए कार्य भी हासिल कर लिए।

139 इंजीनियरों की 'जुगलबंदी' से 587 करोड़ का खेल

सूत्रों और दस्तावेजों के मुताबिक, साल 2020 से 2023 के बीच कुल 960 करोड़ रुपये के जेजेएम कार्यों में धांधली हुई। इसमें से 587 करोड़ रुपये के कार्यों में इन 139 इंजीनियरों की सीधी मिलीभगत सामने आ रही है।

फील्ड में तैनात इन इंजीनियरों ने फर्मों के साथ मिलकर 'माप पुस्तिका' (MB) में फर्जी एंट्री की। DI पाइप की जगह घटिया HDPE पाइप डाल दिए गए। कई जगह तो बिना पाइपलाइन डाले ही पुरानी लाइनों को नया दिखाकर भुगतान उठा लिया गया। हरियाणा से चोरी के पाइप लाकर उन्हें जेजेएम की योजनाओं में खपाया गया और सरकार से नए पाइपों के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। फील्ड के 'खिलाड़ी' अभी भी गिरफ्त से बाहर जिन अधिकारियों को 17 फरवरी को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने तो केवल कागजी वर्क ऑर्डर जारी किए थे। लेकिन भ्रष्टाचार की असली फसल तो फील्ड में इन 139 इंजीनियरों ने काटी। इन्होंने न केवल फर्जी एम.बी. भरी, बल्कि बिना कार्य पूर्ण हुए ही करोड़ों के बिल पास कर दिए। विभाग में चर्चा है कि जब तक इन 139 चेहरों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक न्याय अधूरा है।

फर्जीवाड़े के खेल को मिला संस्थागत संरक्षण

जानकार सूत्रों के अनुसार इस पूरे खेल के पीछे जलदाय विभाग के ही आलाधिकारियों का बड़ा हाथ रहा है। इस फर्जीवाड़े के खेल की नींव भले ही मैसर्स श्याम ट्यूबवैल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन ने रखी थी, लेकिन जैसे-जैसे फर्जीवाड़े का खेल आगे बढ़ता गया, इसमें जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ही नहीं, बल्कि आलाधिकारी से लेकर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री तक शामिल हो गए। फर्म की ओर से योजनाओं में किए गए फर्जीवाड़े का बड़ा हिस्सा इन तक पहुंचाया गया, जिसके चलते गंभीर फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद भी इस मामने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। देशभर में राजस्थान जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार चर्चाओं में आने के बाद केन्द्र सरकार के दखल के बाद अब इस मामले में तीन एजेंसियों की जांच चल रही है, जिसमें ईडी, सीबीआई और एसीबी की जांच चल रही है। इस पूरे खेल के पीछे के 'मास्टरमाइंड' और PHED के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) व वर्तमान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अधिकारी सुबोध अग्रवाल अभी भी फरार चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से कई और सफेदपोश चेहरों से नकाब उतर सकता है।

बड़ा सवाल: क्या ACB अब उन 139 इंजीनियरों के घरों पर दस्तक देगी जिन्होंने जनता के हक के पैसे को फर्मों के साथ मिलकर डकारा? राजस्थान की जनता अब कार्रवाई का इंतजार कर रही है।

राजस्थान के हर जिले में चलेगा 'स्कूल ऑन व्हील', घुमन्तु समाज को मिलेगी सौगात

पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा दांव

जयपुर (विसं)। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' स्थापित किया जाएगा, ताकि पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। यह घोषणा रविवार को जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मन्दिर में आयोजित समाज के महासम्मेलन के दौरान की गई।

शिक्षा और सशक्तिकरण का नया खाका : मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट वर्ष 2026-27 में इस विशेष समुदाय के लिए 'राज पहल' नामक एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 'त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है यह समाज 'सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने घुमन्तु समुदाय के ऐतिहासिक योगदान की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस समाज ने आजादी से पहले गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक किया और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया।

निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे

प्रथम चरण में प्रदेश के सभी जिलों में एक 'स्कूल ऑन व्हील्स' शुरू किया जाएगा। अस्थायी शिक्षा शिविर रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले परिवारों के लिए उनके अस्थायी पड़ाव वाले क्षेत्रों में ही शिक्षा शिविर लगाए जाएंगे। 6 महीने के रेडिनेस कैम्प पलायन के कारण पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा जोड़ने के लिए शैक्षिक संभागों में 'स्कूल रेडिनेस कैम्प' आयोजित होंगे। आवास और छात्रावास घुमन्तु परिवारों को स्थायी ठिकाना देने के लिए आवासीय पट्टे और उनके बच्चों के लिए विशेष छात्रावासों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

अर्थव्यवस्था के रक्षक

सीएम ने याद दिलाया कि बंजारा समुदाय का व्यापारिक कौशल प्राचीन भारतीय व्यापार-मार्गों की रीढ़ रहा है।

शिल्प कला का सम्मान: इस समाज की 'लोहा-शिल्प कला' की गूंज पूरे विश्व में है और यह समाज अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन को समाज के उत्थान की 'संकल्प सभा' करार दिया।

उन्होंने समुदाय के युवाओं से अपील की कि वे देश और प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। साथ ही, उन्होंने समाज के कल्याण से जुड़े अन्य सुझावों पर भी सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

घर के पास कूड़ादान और टॉयलेट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, कोर्ट ने दिए हटाने के आदेश

जस्टिस अमित बंसल का एमसीडी को सख्त निर्देश- 'तुरंत हटाएं अवैध कूड़ेदान और शौचालय'

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि किसी व्यक्ति के घर के ठीक पास सार्वजनिक शौचालय बनाना या खुला कूड़ादान रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिले, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य है।

क्या था पूरा मामला?

जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी वकील रचित गुप्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता रचित गुप्ता ने अदालत को बताया कि उनके घर की दीवार के साथ एक अवैध कूड़ादान और शौचालय बना हुआ है, जिसका लगभग 150 निवासी रोजाना उपयोग करते हैं? इससे क्षेत्र में लगातार दुर्गंध बनी रहती है और अस्वस्थ परिस्थितियों के कारण निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है?

अदालत का एमसीडी को सख्त अल्टीमेटम

अदालत ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमसीडी) की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं।

घर के पास से खुले कूड़ेदान और सार्वजनिक टॉयलेट को बिना देरी के तुरंत हटाया जाए? प्रशासन कचरा संग्रहण के लिए ढके हुए डस्टबिन का उपयोग करे और उन्हें रिहाइशी घरों से उचित दूरी पर स्थापित किया जाए?

सूखे और गीले कचरे के पृथक्करण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए? एमसीडी यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा के साथ कोई समझौता न हो?

क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह आदेश उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा जो शहरी क्षेत्रों में अपने घरों के आसपास अवैध डंपिंग या अव्यवस्थित शौचालयों के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि स्वच्छता बनाए रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिकों का मौलिक अधिकार भी है।

शिक्षा संकट : देश के 5,694 सरकारी स्कूलों में 'जीरो नामांकन', 10 वर्षों में 8% स्कूलों पर लगा ताला

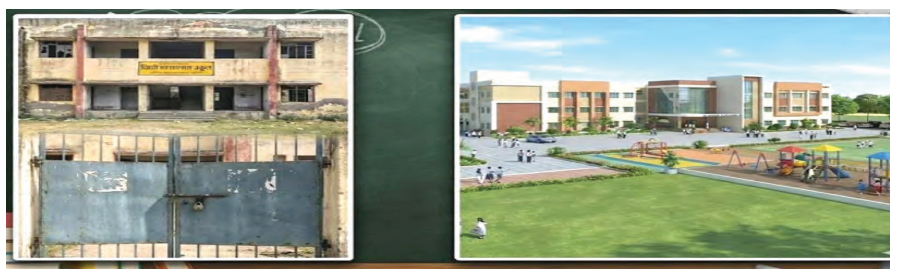

जयपुर (विसं)। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश के 5,694 सरकारी स्कूलों में एक भी छात्र का नामांकन नहीं है। इसके अलावा, 11,149 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार शिक्षा पर सालाना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर रही है।

पिछले एक दशक में देश में 8% सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। अकेले बीते 5 सालों में ही 18,727 स्कूलों को बंद करना पड़ा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 'जीरो नामांकन' नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में स्कूलों की दयनीय स्थिति को दर्शाती है।

राज्य	जीरो नामांकन वाले स्कूल	सिंगल टीचर वाले स्कूल
राजस्थान	1,952	1,571
उत्तर प्रदेश	825	00
मध्य प्रदेश	748	5,987
गुजरात	211	00
छत्तीसगढ़	108	00
महाराष्ट्र	18	44

क्यों खाली हो रहे हैं सरकारी स्कूल : विशेषज्ञों और रिपोर्ट के अनुसार, इस दुर्दशा के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

निजी स्कूलों का दबदबा: गली-गली खुलते निजी स्कूल और बेहतर करियर के वादे अभिभावकों को अपनी ओर खींच रहे हैं।

संसाधनों का अभाव: सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और शिक्षण की गुणवत्ता में कमी देखी गई है।

आर्थिक क्षमता: माता-पिता की बढ़ती आय उन्हें निजी स्कूलों के विकल्प चुनने की ओर ले जा रही है।

बेहतर मार्केटिंग: निजी स्कूल अपनी गतिविधियों और मार्केटिंग में सरकारी तंत्र से कहीं आगे हैं।

आईपीएल 2026: जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों की जीत

एसएमएस स्टेडियम में ही गूंजेगा 'हल्ला बोल'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुलझाया 'सुरक्षा' विवाद
जयपुर में होंगे राजस्थान रॉयल्स के 4 मुकाबले

जयपुर (खेसं)। गुलाबी नगरी के खेल प्रेमियों के लिए लंबे समय से बना संशय अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सकारात्मक पहल के बाद यह तय हो गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू अभियान का बड़ा हिस्सा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही पूरा करेगी। मुख्यमंत्री और फ्रेंचाइजी अध्यक्ष रंजीत बारठाकुर के बीच हुई बैठक में स्टेडियम की सुरक्षा और कानूनी देयता से जुड़े सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है।

पिछले कुछ समय से राजस्थान रॉयल्स और राज्य सरकार के बीच सुरक्षा मानकों को लेकर खींचतान चल रही थी। टाटा प्रोजेक्ट्स की 700 पन्नों की एक स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में एसएमएस स्टेडियम के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में गंभीर कमियों का हवाला दिया गया था। इन कमियों को आधार बनाकर फ्रेंचाइजी ने सरकार से सुरक्षा की कानूनी जिम्मेदारी से छूट मांगी थी। गतिरोध इतना बढ़ गया था कि रॉयल्स ने अपने मैचों को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इन आपत्तियों को नियमित रखरखाव का हिस्सा बताया और अंतत: मुख्यमंत्री के दखल से यह मसला हल हो गया। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान रॉयल्स अपने 7 घरेलू मैचों को दो शहरों के बीच बांटेगी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 4 मुकाबले और गुवाहाटी बरसापारा स्टेडियम में 3 मुकाबले खेलेगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज के पवन ने रॉयल्स, एमएनआईटी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मैदान का निरीक्षण किया है।

छात्रवृत्तियों के लिए खुशखबरी

लंबित आवेदनों का होगा त्वरित निस्तारण : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत

सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के बकाया आवेदनों पर फोकस, फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थान होंगे ब्लैकलिस्ट

जयपुर (विशेष संवाददाता)। *राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों को लेकर शनिवार को कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 तक के सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर लाभ मिल सके।मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन पत्र केवल आपत्तियों या कमियों के कारण लंबित हैं, उनकी तुरंत पूर्ति करवाई जाए। कमियों को दूर कर इन आवेदनों को प्राथमिकता के साथ जिला कार्यालयों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी पात्र छात्र को प्रक्रियात्मक देरी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न रहना पड़े।*

फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों की अब खैर नहीं

विभाग ने शिक्षण संस्थानों के लिए भी सख्त चेतावनी जारी की है। संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदनों की नियमानुसार गहन जांच करने के बाद ही उन्हें आगे भेजें। यदि कोई संस्थान अनियमित या फर्जी आवेदन अग्रेषित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे छात्रवृत्ति पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और अपडेट : मंत्री ने विद्यार्थियों और संस्थानों से अपील की है कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों के लिए निम्नलिखित पोर्टल्स को नियमित रूप से देखते रहें।

ऊर्जा का भविष्य अब स्मार्ट, समावेशी और आम नागरिकों पर केंद्रित

चेयरमैन आरती डोगरा ने राजस्थान बिजली सेक्टर के अनुभव साझा किए

16 फरवरी को AIImpactSummit 2026 के दौरान 'ग्लोबल मिशन ऑन एआई फॉर एनर्जी' (Global Mission on AI for Energy) में शामिल होने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड (REC Limited) द्वारा किया गया था। इस दौरान मैंने #PMKUSUM और विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा (Decentralized Solar) के क्षेत्र में #JaipurDiscom के अनुभवों को साझा किया। साथ ही, इस बात पर चर्चा की कि कैसे 'डिजिटल ट्विन्स' और AI की मदद से डिस्कॉम्स अपनी कार्यप्रणाली को 'रिएक्टिव' (घटना के बाद सुधारना) से बदलकर 'प्रेडिक्टिव' (पूर्वानुमान लगाकर सुधारना) बना सकते हैं, जिससे बिजली की विश्वसनीयता, दक्षता और सेवा वितरण में बड़ा सुधार लाया जा सके।

शिल्पग्राम में उतरी ब्रज की होली और राजस्थानी लोक कलाओं की सतरंगी छटा

संस्कार भारती और पर्यटन विभाग के संगम से महकी मरुधरा की विरासत; साहित्य और आयुर्वेद का भी अनूठा मेल

जयपुर (विशेष संवाददाता)। गुलाबी नगरी के सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र (जेकेके) का शिल्पग्राम शुक्रवार को लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर हो गया। अखिल भारतीय संस्कार भारती और राजस्थान पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय उत्सव 'लोक रंग से उजास: कला संगम-2026' का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले ही दिन शिल्पग्राम में राजस्थानी माटी की खुशबू और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भजनों और लोक नृत्यों से महका मंच : कार्यक्रम का आगाज मांगलिक वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ।

भक्ति संगीत: हण्डु पहलवान और जगत सिंह सुंदरावली ने 'गौ-महिमा' और कृष्ण भजनों की मधुर प्रस्तुति दी। ब्रज की छटा : डीग (भरतपुर) के विष्णु शर्मा और उनके दल ने 'फूलों की होली' और 'चरकुला नृत्य' से फाल्गुनी माहौल बना दिया। लोक गायन : महुआ के श्री कृष्ण गुर्जर एंड पार्टी ने 'लांगुरिया' गीत और जगत सिंह ने 'बम रसिया' की थाप पर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। शिल्पग्राम का यह मेला केवल नाच-गाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां आगंतुकों के लिए कई अन्य आकर्षण भी मौजूद रहे। हस्तशिल्प कला और चित्रकारी की विशेष प्रदर्शनी में राजस्थान की समृद्ध विरासत देखने को मिली। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए आयुर्वेद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 'ज्ञान गंगा प्रकाशन' की स्टॉल पर पाठकों ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का लाभ उठाया।

'लोक चौपाल' : *बौद्धिक विमर्श का केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ 'लोक चौपाल' में नई पीढ़ी को लोक जीवन की वैज्ञानिकता से जोड़ने पर चर्चा हुई।*

मुख्य संयोजक निधीश गोयल ने भारतीय 'लोक' और पश्चिमी 'फोक' के दार्शनिक अंतर को समझाया। प्रथम सत्र में डॉ. इंदु शेखर 'तत्पुरुष', डॉ. विवेक भटनागर और डॉ. तनुजा सिंह ने भारतीय लोक दृष्टि पर विचार साझा किए। दूसरे सत्र में नारायण सिंह राठौड़ 'पीथल', डॉ. गीता सामोर और तनेराज सिंह सोढ़ा ने लोक परंपराओं पर मंथन किया।

199 सीटों की तस्वीर साफ, निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऐसे देखें अपना नाम

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के मतदाताओं के लिए बहुप्रतीक्षित फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया है। इस सूची के जारी होने के साथ ही उन लाखों लोगों का इंतज़ार खत्म हो गया है जिन्होंने नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए आवेदन किया था। विभाग अब जल्द ही राज्य स्तरीय डेटा जारी करेगा, जिससे प्रदेश में कुल वोटर्स और कटे हुए नामों की सही संख्या स्पष्ट हो सकेगी।

नाम खोजने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस : आप निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अपना नाम चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले election.rajasthan.gov.in/Service _Voter_List.asp & पर क्लिक करें। पोर्टल खुलने पर सबसे पहले अपने जिले (District) का चुनाव करें। इसके बाद अपनी विधानसभा सीट (Assembly Seat) को सेलेक्ट करें।

राजस्थान में एसआइआर की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित

पोलिंग बूथ: अंत में अपने पोलिंग बूथ (Polling Booth) के विकल्प पर जाकर फाइनल वोटर लिस्ट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

एसआइआर पुनरीक्षण : ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने से लेकर फाइनल लिस्ट तक की प्रक्रिया में भारी उलटफेर देखने को मिला था।

विवरण	संख्या (लगभग)
ड्राफ्ट लिस्ट में कटे नाम	41.85 लाख
नए नाम जुड़वाने के आवेदन	10.25 लाख से ज्यादा
दस्तावेज मांगे गए वोटर	11 लाख
दावे और आपत्तियां	1.06 लाख

सियासी विवाद और फर्जीवाड़े के आरोप : एसआइआर प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में जमकर राजनीति भी हुई। कांग्रेस ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की तारीख बढ़ाने पर सख्त एतराज जताया था। अलवर समेत कई अन्य जिलों में हजारों ऐसे फॉर्म सामने आए थे, जिनमें मतदाताओं के नाम और हस्ताक्षर तक फर्जी पाए गए थे। इन्ही शिकायतों के निस्तारण के बाद अब निर्वाचन विभाग ने अंतिम सूची सार्वजनिक की है।

आरटीई एडमिशन में 'डिजिटल स्ट्राइक': फर्जीवाड़ा किया तो जेल के साथ देनी होगी दोगुनी फीस

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला : फर्जी आय प्रमाण पत्र पर नकेल, पहली बार पेन कार्ड से जुड़ी पात्रता

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निशुल्क प्रवेश पाने की राह अब 'जुगाड़' करने वालों के लिए मुश्किल होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए जारी गाइडलाइंस में पारदर्शिता लाने के लिए बेहद सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि किसी अभिभावक ने गलत जानकारी देकर बच्चे का एडमिशन कराया, तो न केवल प्रवेश रद्द होगा, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर स्कूल की फीस की दोगुनी राशि वसूली जाएगी। इस बार आवेदन प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें आवेदन में नंबर देना ही होगा। विभाग इस नंबर के जरिए अभिभावक की वास्तविक आय की क्रास-चेकिंग करेगा। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए फिलहाल इसे वैकल्पिक रखा गया है ताकि गरीब परिवार परेशान न हों।

स्कूलों को अधिकार दिया गया है कि यदि उन्हें किसी अभिभावक की आर्थिक स्थिति को देखकर आय प्रमाण पत्र पर संदेह होता है, तो वे विभाग को शिकायत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विभाग अभिभावक से इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकता है।

4 कक्षाओं में प्रवेश, स्कूलों पर एफआईआर की जिम्मेदारी : इस साल आरटीई का दायरा बढ़ाते हुए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली (1ह्यह्ल) कक्षा को शामिल किया गया है। हालांकि, नियमों के पालन की जिम्मेदारी निजी स्कूलों पर भी डाली गई है। फर्जीवाड़े के मामलों में स्नढ्ढक्र दर्ज कराने का उत्तरदायित्व स्कूल प्रशासन का होगा।

ई-मित्र और फर्जी मुहरों पर पैनी नजर : शिक्षा विभाग ने ई-मित्र संचालकों को भी कड़ी चेतावनी दी है। अक्सर शिकायतें आती हैं कि ई-मित्र केंद्रों पर फर्जी गजेटेड अधिकारियों की मुहर लगाकर आय प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं। विभाग ने साफ किया है कि जांच में मिलीभगत पाए जाने पर ई-मित्र का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ संचालक को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी।

'फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फ्री शिक्षा का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं।'

– **चंद्र किरण पंवार,** सहायक निदेशक, शिक्षा विभाग नर्सरी, एतकेजी, यूकेजी और वीएसटी

पार्किंग निगलने वाले व्यापारियों की अब खैर नहीं

डीसीपी ट्रैफिक की चेतावनी : सात दिन में पार्किंग खाली करो वरना दर्ज होगा मुकदमा

गुलाबी नगरी में ट्रैफिक जाम का 'डेथ वॉरंट' : सड़कों पर वाहन खड़े किए तो होंगे जब्त

__जयपुर (विशेष संवाददाता)।__ जयपुर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या अब एक नासूर बन चुकी है। सड़कों और बाजारों में स्थित रेस्टोरेंट, मॉल, मैरिज गार्डन और स्कूलों के पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण वाहन सड़कों पर ही खड़े हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के ताज़ा सर्वे में शहर के चारों ज़ोन में ऐसे 84 'जाम पॉइंट' सामने आए हैं, जहाँ अवैध पार्किंग न केवल यातायात को बाधित कर रही है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण का भी बड़ा कारण बन रही है। जोन के अनुसार जाम की 'कुंडली' ट्रैफिक पुलिस ने शहर को चार मुख्य जोन में बांटकर जाम के हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं।

डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरडा ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जिन संस्थानों ने स्वीकृत पार्किंग की जगह दुकानें या रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर पार्किंग स्थल खाली नहीं किया गया, तो संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

जोन	जाम पॉइंट	मुख्य प्रभावित इलाके
पश्चिम ज़ोन	27 पॉइंट	बनीपार्क, वैशाली नगर, झोटवाड़ा और खातीपुरा (ढाबे, अस्पताल और मैरिज गार्डन
पूर्व जोन	26 पॉइंट	टोंक रोड, जेएलएन मार्ग और सांगानेर (भोजनालयों और बड़े स्कूलों के बाहर पार्किंग संकट) के बाहर जाम)
दक्षिण जोन	23 पॉइंट	एमआई रोड, अजमेर रोड और मानसरोवर (मॉल, स्कूलों और होटलों के सामने अवैध पार्किंग)
उत्तर ज़ोन	08 पॉइंट	चारदीवारी क्षेत्र (रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल्स के बाहर सड़क पर खड़े वाहन)

__जब्ती की कार्रवाई :__ सड़क पर अवैध पार्किंग करने वालों पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि वाहन को भी जब्त किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड को समाधान के लिए कुछ अहम सुझाव भेजे हैं-

__सख्त 'नो पार्किंग':__ प्रमुख मार्गों पर 'नो पार्किंग' जोन का सख्ती से पालन करवाया जाए।

__पीपीप मॉडल:__ व्यस्त बाजारों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर मल्टीलेवल पार्किंग विकसित की जाए।

__मैरिज गार्डन के लिए नियम:__ मैरिज गार्डनों के लिए स्वयं की पार्किंग सुनिश्चित करना अब अनिवार्य होगा।

पार्किंग की जगह व्यापार करना कानूनन अपराध है। हम शहर को जाम मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अब केवल जुर्माना नहीं, बल्कि सीधे कानूनी कार्वाई (एफआईआर) की जाएगी।

– सुमित मेहरडा, डीसीपी ट्रैफिक

मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश

पंचायत-निकाय चुनाव में 'जमीनी योद्धाओं' को मिलेगा सम्मान

अजमेर संभाग की बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा-'टिकट वितरण में सिफारिश नहीं, समर्पण बनेगा आधार'

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव 2026 की बिसात बिछ चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 'अपनों' का मतलब 'रसूखदार' नहीं, बल्कि 'जमीनी कार्यकर्ता' होगा। अजमेर संभाग के पदाधिकारियों के साथ टोंक में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी चुनावों के लिए जीत का मंत्र फूंका और कार्यकर्ताओं को टिकट के लिए आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ताकत किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि उसके निष्ठावान कार्यकर्ता में है। आगामी चुनावों में उन्हीं चेहरों पर दांव खेला जाएगा जो जनता के बीच सक्रिय हैं।

अंतिम छोर तक पहुंच: 'विकसित राजस्थान' के विजन को सफल बनाने के लिए सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है।

तालमेल ही ताकत : सरकार के बजट और संगठन की मजबूती के बीच समन्वय ही चुनाव में जीत सुनिश्चित करेगा।

पीएम मोदी का विजन: 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए राजस्थान के हर निकाय और पंचायत में भाजपा का परचम जरूरी है।

सुशासन का नया अध्याय : अब एसीएस और सचिव उठाएंगे जनता का फोन

राजस्थान संपर्क (181) पर आमजन की शिकायतें सुनेंगे प्रदेश के शीर्ष अधिकारी मुख्यमंत्री ने 35 सीनियर आईएएस की कॉल सेंटर पर लगाई ड्यूटी

__जयपुर (विशेष संवाददाता)।__ राजस्थान सरकार ने जनसुनवाई की पारंपरिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए अधिकारियों की सीधे जनता के प्रति जवाबदेही तय की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के 35 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अब सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर (181) पर स्वयं मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

__शिकायतों का निस्तारण और व्यक्तिगत मॉनिटरिंग :__ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ड्यूटी रोस्टर में शामिल प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को अपनी शिफ्ट के दौरान कम से कम 10 कॉल रिसीव करने होंगे। अधिकारी न केवल नई समस्याओं का पंजीकरण करेंगे, बल्कि संपर्क पोर्टल पर लंबे समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग भी करेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य निचले प्रशासन में मुस्तैदी लाना और 'पब्लिक फर्स्ट' की नीति को धरातल पर उतारना है।

__सीएम का औचक निरीक्षण बना आधार :__ इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे मुख्यमंत्री का वह औचक निरीक्षण है, जिसमें उन्होंने स्वयं हेडफोन लगाकर शिकायतकर्ताओं से संवाद किया था। सरकार का मानना है कि जब अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी सीधे जनता से बात करेंगे, तो जिला कलेक्टर और तहसीलदार स्तर पर फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी।

__जानें कब, कौन से आईएएस अफसर रहेंगे ड्यूटी पर :__ यह सघन अभियान 4 मार्च 2026 से शुरू होकर 28 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जाएगा। ड्यूटी चार्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती इस प्रकार रहेगी-

Sr.No	Officer	Date
1	Shri Abhay Kumar	04.03.2026
2	Smt. Aparna Arora	05.03.2026
3	Shri Shikhar Agarwal	06.03.2026
4	Shri Sandeep Verma	09.03.2026
5	Shri Kuldeep Ranka	10.03.2026
6	Smt. Shreya Guha	11.03.2026
7	Shri Anand Kumar	12.03.2026
8	Shri Praveen Gupta	13.03.2026
9	Shri Bhaskar Sawant	16.03.2026
10	Shri Ashwini Bhagat	17.03.2026
11	Shri Kunji Lal Meena	18.03.2026
12	Shri Ajitabh Sharma	19.03.2026
13	Shri Dinesh Kumar	23.03.2026
14	Smt. Gayatri Rathore	24.03.2026
15	Shri Vaibhav Galriya	25.03.2026
16	Shri T. Ravikant	27.03.2026
17	Shri Subir Kumar	30.03.2026
18	Shri Bhawani Singh Detha	01.04.2026
19	Smt. Manju Rajpal	02.04.2026
20	Dr. Debashish Prushti	06.04.2026
21	Shri Naveen Jain	07.04.2026
22	Shri Krishna Kunal	08.04.2026
23	Shri Neeraj K. Pawan	09.04.2026
24	Shri Raghavendra Kachwal	10.04.2026
25	Shri Ravi Jain	13.04.2026
26	Shri Samit Sharma	15.04.2026
27	Shri Ravi Kumar Surpur	16.04.2026
28	Shri Ambrish Kumar	17.04.2026
29	Dr. Joga Ram	20.04.2026
30	Shri P. Ramesh	21.04.2026
31	Shri V. Saravan Kumar	22.04.2026
32	Smt. Anandi	23.04.2026
33	Smt. Shuchi Tyagi	24.04.2026
34	Smt. Archana Singh	27.04.2026
35	Shri Ravindra Goswami	28.04.2026

साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन : प्रदेश में खुलेंगे विशेष साइबर कोर्ट : सीएम

जस्टिस सूर्यकांत ने 'डिजिटल अरेस्ट' को बताया धोखाधड़ी

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'साइबर सुरक्षा- जागरूकता, संरक्षण एवं न्याय तक समावेशी पहुंच' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल युग की चुनौतियों और समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। जस्टिस सूर्यकांत ने 'डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं' उन्होंने डिजिटल सुरक्षा को संस्थागत विश्वास का विषय बताया।

धोखाधड़ी से सावधान : उन्होंने स्पष्ट किया कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई भी न्यायिक प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है और यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है।

सुरक्षा का मंत्र : उन्होंने पुरानी सीख 'हमेशा सोचकर बोलो, समझकर कार्य करो' को आधुनिक डिजिटल दुनिया के लिए अनिवार्य बताया, जहां एक गलत क्लिक भारी नुकसान करा सकता है?

नागरिक शिक्षा : साइबर सुरक्षा को दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए इसे नागरिक शिक्षा का हिस्सा बनाना आवश्यक है?

सुलभ न्याय : उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) द्वारा न्याय को सुलभ बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों की सराहना की?

मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा : प्रदेश में स्थापित होंगे 'स्पेशल साइबर कोर्ट' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन में राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं उन्होंने प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और त्वरित न्याय के लिए विशेष साइबर कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने

बताया कि 'ऑपरेशन एंटी वायरस' के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है? साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए 'राजस्थान साइबर क्राइम कण्ट्रोल सेण्टर' (आरफॉरसी) की स्थापना की जा रही है। सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म और पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया:

ई-समाधान: ऑनलाइन मध्यस्थता एवं लोक अदालत प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग?

ई-कोर्ट्स का विस्तार: दूर-दराज के क्षेत्रों तक त्वरित न्याय पहुँचाने के लिए ई-कोर्ट पोर्टल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रभावी उपयोग?

महत्वपूर्ण प्रकाशन: मध्यस्थता पर हैंडबुक, 'महिला पंचायत पैन राजस्थान ', लीगल सर्विसेज रेडी रेकनर 2026 और साइबर जागरूकता हैंडबुक का विमोचन किया गया?

उड़ान 2.0: स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत दिव्यांग विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया?

सावधान! सैलरी बढ़ने की खुशी न बदल जाए गम में

व्हाट्सएप पर 'सैलरी कैलकुलेट' का लालच देकर मोबाइल का एक्सेस ले रहे ठग, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

राजस्थान में '8th CPC' के नाम पर बड़ा स्कैम, ऐसे खाली हो रहे खाते

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी जारी की गई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उत्सुकता को साइबर ठगों ने अपना हथियार बना लिया है। राज्य की साइबर पुलिस ने बताया कि ठग 'सैलरी कैलकुलेटर' के नाम पर एक खतरनाक सॉफ्टवेयर के जरिए बैंक खाते खाली कर रहे हैं।

कैसे बुना जा रहा है ठगी का जाल?

डीजीपी (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने खुलासा किया कि ठग व्हाट्सएप पर एक लुभावना मैसेज भेज रहे हैं। इसमें दावा किया जाता है कि कर्मचारी घर बैठे अपनी नई

संभावित सैलरी चेक कर सकते हैं।

फर्जी फाइल: मैसेज के साथ 8th_CPC_Calculator.apk नाम की एक फाइल अटैच होती है। जैसे ही कोई इस फाइल को डाउनलोड कर इंस्टॉल करते हैं, ठगों को उस मोबाइल का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद ठग आपके एसएमएस, ओटीपी कैमरा और गैलरी तक पहुंच जाते हैं और आपकी नेट बैंकिंग की जानकारी चुराकर खाते से पैसे साफ कर देते हैं। बचाव के लिए राजस्थान पुलिस ने कर्मचारियों से इन चार नियमों को गांठ बांधने की अपील की है-

आधिकारिक स्त्रोत: सरकार कभी भी व्हाट्सएप पर सॉफ्टवेयर या एपीके (APK) फाइल नहीं भेजती। सैलरी संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर ही देखें।

अनजान लिंक पर 'No': किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज या शॉर्ट लिंक पर क्लिक न करें।

सिर्फ आधिकारिक स्टोर: कोई भी ऐप केवल 'Google Play Store' या 'Apple App Store' से ही डाउनलोड करें।

रिपोर्ट और ब्लॉक: ऐसा संदिग्ध मैसेज मिलते ही उसे तुरंत डिलीट करें और उस नंबर को व्हाट्सएप पर 'Report & Block' करें।

यदि ठगी का शिकार हो जाएं : यदि आप अनजाने में इस जाल में फंस गए हैं, तो 'गोल्डन आवर' (शुरुआती 1-2 घंटे) में की गई कार्रवाई आपके पैसे बचा सकती है। नेशनल हेल्पलाइन: तुरंत 1930 पर कॉल करें। राजस्थान पुलिस हेल्पडेस्क: 9256001930 या 9257510100 पर संपर्क करें। ऑनलाइन शिकायत : आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाखड़

राजस्थान के लाल को 55 साल में पहली बार मिली कमान

जयपुर (विसं)। राजस्थान की छात्र राजनीति ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को संगठन का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनएसयूआई के 55 साल के इतिहास में यह पहला अवसर है जब संगठन का सर्वोच्च पद प्रदेश के किसी नेता को मिला है।

संघर्ष की मिसाल: जिस स्कूल में पिता ने की मजदूरी, वहीं से शुरू हुई शिक्षा विनोद जाखड़ का जीवन कड़े संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी है। विनोद जाखड़ का जन्म जयपुर के पास एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक मिस्त्री (प्लास्टर का काम करने वाले) हैं।

जाखड़ की राजनीति में चमक 2018 के राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव से शुरू हुई। उस समय एनएसयूआई ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया था। हार मानने के बजाय विनोद ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और न केवल जीत हासिल की, बल्कि राजस्थान कॉलेज के पहले दलित अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया। इसी जीवटता और संघर्ष क्षमता के कारण वे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के 'युवा विजन' के भरोसेमंद पात्र बने।

सम्पादकीय

ट्रंप की मनमानी पर रोक

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी हेकड़ी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया, जिससे उनकी मनमानी पर रोक लगी। यह फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, खासकर मध्यावधि चुनावों से पहले।

मुझे टैरिफ से प्यार है और यह मेरा पसंदीदा शब्द है, ऐसा कहकर इतराने वाले राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हेकड़ी निकाल दी। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत समेत तमाम देशों पर थोपे गए टैरिफ को अवैध करार दिया। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के उन दो न्यायाधीशों ने भी ट्रंप की टैरिफ नीति को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर माना, जिनकी नियुक्ति स्वयं उन्होंने की थी। इससे पता चलता है कि ट्रंप टैरिफ के मामले में किस तरह नियम-कानूनों की घोर अनदेखी करने में लगे हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल ट्रंप की टैरिफ नीति की हवा निकालने वाला, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने वाला भी है, क्योंकि वे एक तरह से अवैधानिक काम करते पकड़े गए। ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के जरिये अपने समर्थकों के बीच यह माहौल बनाने में जुटे थे कि वे अमेरिका को मालामाल कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी ठगे जाने का अहसास होगा और वह भी ऐसे समय, जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की कम होती लोकप्रियता को और कम करने वाला है और इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन यह भी तय है कि वे चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद एक कार्यकारी आदेश जारी कर सभी देशों पर दस प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि इसकी अवधि पांच महीने ही रहेगी, लेकिन इस बीच ट्रंप अन्य उपायों का सहारा लेने की कोशिश कर सकते हैं।

ट्रंप अमेरिका के साथ अनुचित एवं भेदभावपूर्ण व्यापार का आरोप लगाकर कुछ देशों पर अतिरिक्त टैरिफ थोप सकते हैं। इसी तरह वैसे आयात पर भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, जिनसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा हो, लेकिन इन उपायों को अमल में लाने के लिए उन्हें जांच के जरिये यह सिद्ध करना होगा कि वास्तव में अमुक-अमुक देश अनुचित व्यापार नीति पर चल रहे हैं या फिर अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बने उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

चूंकि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारे के बहाने अपने स्वार्थों को पूरा करने और अपनी छवि चमकाने के फेर में रहते हैं, इसलिए टैरिफ से इतर मामलों में मनमाने, अप्रत्याशित और विश्व को मुश्किल में डालने वाले फैसले ले सकते हैं। अपने लोगों का ध्यान बंटाने के लिए वे ईरान पर हमला कर सकते हैं। वे उसकी घेराबंदी करने में जुटे ही हैं। वे क्यूबा और कुछ अन्य देशों पर भी अपनी निगाह टेढ़ी कर सकते हैं। जो भी हो, भारत को उनसे तब भी सावधान रहना होगा, जब अमेरिका से अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए, क्योंकि वे भरोसे के काबिल नहीं रह गए हैं।

विचार-1

रंग, रस और रसमय परंपराओं का अद्भुत उत्सव : होली

होली का मूल उद्देश्य होलिका की कथा के अनुसार असत्य पर सत्य की विजय समाज में प्रेम, समरसता और समानता का भाव,राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम का उत्सव, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के नवोत्सव का स्वागत, ब्रज में होली अहंकार के दहन और प्रेम का प्रतीक है।

■ महंत दीपक वल्लभ गोस्वामी

होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि कृष्ण-भक्ति, लोक-संस्कृति और रस परंपरा का जीवंत उत्सव है। वृन्दावन , बरसाना , नंदगाव और मथुरा में फाल्गुन मास आते ही पूरा ब्रज राधा-कृष्ण के रंग में सराबोर हो उठता है। ब्रज के साथ में सम्पूर्ण देश में होली अनेक रूपों में खेली जाती है-मुख्यत:

लट्ठमार होली (बरसाना-नंदगांव) : बरसाना की लट्ठमार होली विश्वविख्यात है। परंपरा है कि नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और गोपियां लाठियों से उनका हास्य-विनोद में स्वागत करती हैं, पुरुष ढाल लेकर बचाव करते हैं।

पूरा वातावरण फाग गीत, ढोल, नगाड़ों और 'राधे-राधे' के जयघोष से गूंज उठता है। पुरुष महिलाओं से हार जाते है तो उन्हें महिलाओं की पोशाक पहनाकर नचाते हैं। बरसाने की गोपियाँ हास्य करती हैं।

डोलची होली : यह विशेष रूप से नंदगाव में प्रचलित है और अपनी अनोखी शैली के कारण ब्रज की अन्य होलियों से अलग पहचान रखती है।'डोलची' अर्थात छोटी बाल्टी या पात्र। इस होली में लाठियों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि रंग से भरी डोलचियों से एक-दूसरे पर रंग डाला जाता है। फाल्गुन के दिनों में जब नंदगांव की गलियाँ गुलाल और अबीर से सराबोर होती हैं, तब पुरुष और महिलाएँ परंपरागत वेशभूषा में सजे हुए रंगों की डोलचियाँ लेकर उत्सव में शामिल होते हैं।

फूलों की होली : वृन्दावन के मंदिरों के अलावा देश के अनेक मंदिरों में फूलों की वर्षा के साथ होली खेली जाती है। विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। जहाँ हज़ारों किलो फूलों की रंग बिरंगी पत्तियों को हवा में एक दूसरे पर उड़ाते हुए सभी कृष्ण राधा के भजनों में झूमते हैं नाचते गाते हैं। मिठाइयाँ खाते हैं खिलाते हैं।

विधवा होली : रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए विधवा होली का विशेष महत्व हैं। वृंदावन में सफेद वस्त्रों में विधवा महिलाओं पर रंग बिरंगी गुलाल उड़ाकर दुनियां को सामाजिक समरसता का सन्देश देती हैं। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति हो भक्ति और आनंद पर किसी का एकाधिकार नहीं है बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक समानता का उत्सव है। ये सुन्दर दृश्य बताता है की कुंठित समाज के मन से भेद भाव की कालीमा धुल जाती है और सभी प्रेम के रंग में रंग जाते हैं ब्रज की संस्कृत पूरे विश्व को ये सन्देश देती है की हमारे देश की संस्कृति हर वर्ग में प्रेम और समानता का सन्देश देती है। यह परंपरा अब नई चेतना का प्रतीक बन चुकी है।

हुरंगा होली, दाऊजी मंदिर की हुरंगा होली में उत्साह और उल्लास चरम पर होता है।'हुरंगा' शब्द ही उल्लास, हुड़दंग और मुक्त आनंद का संकेत देता है। इस दिन मंदिर प्रांगण में पुरुष और महिलाएँ रंग-गुलाल के बीच फाग गाते हुए एकत्र होते हैं। परंपरा के अनुसार महिलाएँ पुरुषों पर चन्दन केसर का रंग डालती हैं, उनके वस्त्र पकड़कर हास्यपूर्ण छेड़छाड़ करती हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें 'पराजित' करती हैं। ढोल, नगाड़े, मृदंग और 'जय जय श्री कृष्ण नन्द के लाला की जय ' के जयघोष से पूरा वातावरण गूंज उठता है।

होली का मूल उद्देश्य होलिका की कथा के अनुसार असत्य पर सत्य की विजय समाज में प्रेम, समरसता और समानता का भाव,राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम का उत्सव, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के नवोत्सव का स्वागत,ब्रज में होली अहंकार के दहन और प्रेम का प्रतीक है। रसखान की दृष्टि में ब्रज की होली का अद्भुत चित्रण मिलता है-

धूरि भरे अति शोभित श्याम जू,
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी।
खेलत खात फिरैं अँगना,
पग पैंजनी बाजति पीरी कछोटी॥
मानुष हौं तो वही रसखान,
बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन।

धूल (गुलाल) से लिपटे हुए श्रीकृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर की चोटी भी बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही है। वे आँगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में बंधी पायल मधुर ध्वनि कर रही है और पीतवर्णी कछोटी (पीली धोती) उनकी शोभा बढ़ा रही है।

सूरदास अपनी काव्य-धारा में कहते हैं-

आजु ब्रज में होरी रे रसिया।
होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया॥

आज ब्रज में होली खेली जा रही है, हे रसिक कृष्ण! आप प्रेमपूर्वक और चंचलता से होली खेल रहे हैं।

उड़त गुलाल लाल भए बदरा।
रंग बरसत झोरी रे रसिया॥

गुलाल उड़कर आकाश को लाल कर रहा है, मानो बादल भी रंगीन हो गए हों। आपकी झोली से रंगों की वर्षा हो रही है।

वल्लभ संप्रदाय और बालकृष्ण की फूलों की होली

वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टिमार्ग वल्लभ संप्रदाय में बालकृष्ण की सेवा प्रमुख है। कृष्ण को नंदलाल बाल स्वरूप में सजाकर फूलों, केसर और चंदन से होली खेली जाती है।

यहाँ बधाई भजन और षोडश गीत सेवा के सोलह चरणों से जुड़े पद गाए जाते हैं:

आज ब्रज में होरी रे रसिया
फाग खेलत नंदलाल बिरज में

इन भजनों में वात्सल्य, माधुर्य और भक्ति का सुंदर संगम दिखाई देता है। ब्रज की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और भक्ति का उत्सव है। यहाँ होली में धर्म, कला, संगीत और लोक परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है।

रंगों से भी अधिक गहरा है वह प्रेम, जो ब्रज की गलियों में राधा-कृष्ण के नाम से आज भी बहता है। यही ब्रज की होली की आत्मा है जहाँ रंग भी भक्ति बन जाते हैं और उत्सव भी साधना।

होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि हृदयों के मिलन का महापर्व है। ब्रज की गलियों से उठता अबीर-गुलाल सम्पूर्ण विश्व में फैलता हैं और हमें स्मरण कराता है कि जीवन का सच्चा रंग प्रेम, समरसता और भक्ति में ही है। राधा-कृष्ण की लीलाओं से आलोकित यह पर्व हमें अहंकार त्यागकर अपनत्व अपनाने का संदेश देता है।

जब चंदन-केसर की सुगंध, फाग के स्वर चंग ढ़ोल नगाड़ों और 'राधे-राधे' का जयघोष वातावरण में घुलता है, तब होली केवल एक तिथि नहीं रहती वह संस्कृति, करुणा और आनंद का उत्सव बन जाती है। यही होली की आत्मा है, और यही भारतीय परंपरा का अमिट रंग।

(लेखक सनातन अध्यात्म गुरु हैं)

एक अद्भुत यात्रा

दिल्ली का नवाब, ब्रज का भक्त : रसखान

■ नाज़िम नक़वी

आज जब समाज बार-बार पहचान, परंपरा और भिन्नताओं के प्रश्नों से जूझता है, तब रसखान का जीवन एक शांत लेकिन गहरा संदेश देता है- संस्कृति सीमाएँ नहीं बनाती, सेतु बनाती है। और शायद इसी कारण ब्रज में आज भी कोई यह नहीं पूछता कि रसखान कहाँ से आए थे! वहाँ बस इतना कहा जाता है वो हमारे थे, हमारे है और हमारे रहेंगे।

16वीं सदी की दिल्ली सत्ता की चमक, दरबार की भाषा फारसी, और राजवंशों की राजनीति से भरा हुआ वातावरण। इसी परिवेश में लगभग 1533 ईस्वी के आसपास एक बालक जन्म लेता है सैयद इब्राहीम, जिन्हें इतिहास और साहित्य आज रसखान के नाम से जानता है। यह कथा केवल एक कवि की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने सत्ता की नश्वरता को देखा, अनुभव किया, और अंतत: प्रेम को अपना अंतिम सत्य चुना।

रसखान का प्रारंभिक जीवन दिल्ली की उस दुनिया में बीता जहाँ पठान शासन का प्रभाव था। वे शिक्षित परिवार से थे, फारसी और अरबी भाषा पर उनकी पकड़ थी। वे उस सांस्कृतिक वातावरण में पले-बढ़े जहाँ इस्लामी बौद्धिक परंपरा और दरबारी संस्कृति का प्रभुत्व था। किंतु इतिहास की धारा स्थिर नहीं रहती। सन् 1555 ईस्वी में जब सूर (पठान) वंश का पतन हुआ और दिल्ली हिंसा तथा राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र बनी, तो इस घटना ने एक संवेदनशील युवा मन को भीतर तक प्रभावित किया।

रसखान का प्रसिद्ध दोहा इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है

देखि गदर हित साहिबी,
दिल्ली नगर मसान।
छिनहिं बादशा वंश की,
उसक छाड़ि रसखान॥

यदि उस समय उनकी आयु लगभग बाईस वर्ष रही हो, तो यह अनुमान करना कठिन नहीं कि सत्ता की चकाचौंध के पीछे छिपी अस्थिरता और क्रूरता ने उनके भीतर प्रश्नों का एक संसार जगा दिया होगा। यह केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं था; यह आत्मा की बेचैनी का आरंभ था।

यहीं से रसखान की यात्रा प्रारंभ होती है दिल्ली से ब्रज की ओर। यह केवल भौगोलिक स्थानांतरण नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन था। जहाँ दिल्ली में सत्ता और वैभव था, वहीं ब्रज में माधुर्य, लीला और आत्मीयता और प्रेम का संसार था। ब्रज की भूमि पर ईश्वर राजा नहीं, बालक है; वह सिंहासन पर नहीं, गलियों में खेलता है; वह भय नहीं जगाता, प्रेम जगाता है।

परंपरागत कथाओं के अनुसार, रसखान श्रीकृष्ण के रूप-माधुर्य और ब्रज-लीला से अत्यंत प्रभावित हुए। वे वृंदावन पहुँचे। कहा जाता है कि जब उन्होंने ठाकुरजी के बाल रूप के दर्शन किए, तो उनका मन पूर्णत: परिवर्तित हो गया। यह प्रसंग केवल भक्तिपरक आख्यान नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक अनुभव का प्रतीक है जिसमें सौंदर्य आध्यात्मिकता का माध्यम बन जाता है। रसखान के जीवन-रूपांतरण को समझने के लिए पुष्टिमार्ग का संदर्भ अनिवार्य है। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित पुष्टिमार्ग, जिसे शुद्धाद्वैत वेदांत की परंपरा भी कहा जाता है, भक्ति को ईश्वर-कृपा पर आधारित मानता है। यहाँ साधना का केंद्र त्याग नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण समर्पण है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ (गुसाईंजी) ने इस परंपरा का व्यापक विस्तार किया और ब्रज-भक्ति की सांस्कृतिक संरचना को सुदृढ़ किया।

परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, रसखान ने गुसाईंजी विट्ठलनाथ से पुष्टिमार्गीय दीक्षा—'ब्रह्म-संबंध'—ग्रहण किया। पुष्टिमार्ग में दीक्षा का अर्थ केवल धार्मिक संबद्धता नहीं है; यह स्वयं को पूर्णत: श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित करने की प्रतिज्ञा है। रसखान ने यह समर्पण केवल शब्दों में नहीं, अपने जीवन और काव्य में साकार किया। उनका व्यक्तित्व सत्ता-केंद्रित पहचान से हटकर प्रेम-केंद्रित चेतना में रूपांतरित हो गया।

यहाँ रसखान पुनर्जन्म की बात करते हुए बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं .. कहते हैं -

मानुष हौं तो वही रसखानि बसौंब्रज
गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बसु
मेरा चरौं नित नंद की धेनु मँझारन।
पाहन हौं तो वही गिरि को जो
धर्यौ कर छत्र पुरंदर धारन।
जो खग हौं तौ बसेरो करौं
मिलि कालिंदी-कूल-कदंब की डारन॥

रसखान कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य-योनि मिले तो 'मैं वही मनुष्य बनूँ जिसे ब्रज और गोकुल गाँव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले.. अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, ईश्वर जैसी योनि चाहेगा, दे देगा, इसलिए यदि मुझे पशु-योनि मिले तो मेरा जन्म ब्रज या गोकुल में ही हो, ताकि मुझे नित्य नंद की गायों को चराने का सौभाग्य प्राप्त हो सके.. और अगर मुझे पत्थर-योनि मिले तो मैं उसी पर्वत का एक भाग बनूँ जिसे कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भाँति उठा लिया था.. और यदि मुझे पक्षी-योनि मिले, तो मैं ब्रज में ही जन्म पाऊँ ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम्ब वृक्ष की डालियों पर निवास कर सकूँ।'

उनकी काव्य-भाषा इस परिवर्तन का साक्ष्य है। फ़ारसी और अरबी के विद्वान होते हुए भी उन्होंने ब्रजभाषा को चुना। यह चयन साहित्यिक सुविधा नहीं, सांस्कृतिक आत्मसात था। मानुष हौं तो वही रसखानि, बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन यह पंक्ति केवल पुनर्जन्म की कामना नहीं, बल्कि उस भाव-जगत की स्वीकृति है जिसमें कवि स्वयं को ब्रज के साधारण ग्वाल-बालों के बीच रखना चाहता है। यहाँ अहंकार का लोप है और प्रेम की पराकाष्ठा है ।

रसखान की दो प्रमुख कृतियाँ प्रेमवाटिका' और सुजान रसखान—उनकी आध्यात्मिक संवेदना का दर्पण हैं। प्रेमवाटिका विशेष रूप से प्रेम के दार्शनिक आयामों का काव्यात्मक निरूपण है। इसमें प्रेम केवल लौकिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मध्य का सेतु है। रसखान की दृष्टि में प्रेम ही वह तत्व है जो विभाजन को मिटाता है और व्यक्ति को व्यापक सांस्कृतिक चेतना से जोड़ता है।

सेस गनेस महेस दिनेस
सुरेसहु जाहि निरंतर गावै।
जाहि अनादि अनंत अखंड
अछेद अभेद सुबेद बतावै॥
नारद से सुक व्यास रटै
पचि हारे तऊ पुनि पार न पावै।
ताहि अहीर की छोहरिया
छछिया भरि छाछ पै नाच नचावै॥

रसखान कहते हैं कि 'जिस कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य, इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं.. वेद जिसके स्वरूप का निश्चित ज्ञान प्राप्त न करके उसे अनादि, अनंत, अखंड अछेद्य आदि विशेषणों से युक्त करते हैं.. नारद, शुकदेव और व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता नहीं लगा पाते उसी कृष्ण को अहीर की लड़कियाँ छाछिया-भर छाछ के लिए नाच नचाती हैं।'

उनका जीवन इस तथ्य का प्रमाण है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा केवल सहिष्णुता तक सीमित नहीं रही; उसने आत्मसात करने की क्षमता दिखाई है। रसखान को ब्रज ने अपनाया, और ब्रज नें रसखान को अपना लिया। यह द्विपक्षीय स्वीकृति ही उनकी कथा को अद्वितीय बनाती है। रसखान की कथा हमें यह सिखाती है कि पहचान स्थिर नहीं होती; वह अनुभव से बदलती है। सत्ता का वैभव क्षणभंगुर है, पर प्रेम की अनुभूति स्थायी। दिल्ली का वह नवयुवक जिसने सत्ता के पतन को देखा, अंतत: ब्रज की गलियों में प्रेम का अमर गायक बन गया।

आज जब समाज बार-बार पहचान, परंपरा और भिन्नताओं के प्रश्नों से जूझता है, तब रसखान का जीवन एक शांत लेकिन गहरा संदेश देता है—संस्कृति सीमाएँ नहीं बनाती, सेतु बनाती है। और शायद इसी कारण ब्रज में आज भी कोई यह नहीं पूछता कि रसखान कहाँ से आए थे! वहाँ बस इतना कहा जाता है वो हमारे थे, हमारे है और हमारे रहेंगे।

(लेखक देश के जाने माने साहित्यकार और उर्दू शायर हैं)

सरकारी और वन भूमि पर बसे किसानों को भी पहली बार मिलेगा मुआवजा : रावत

बारां-झालावाड़ के किसानों के लिए बड़ी सौगात : परवन परियोजना की नई DPR अंतिम चरण में

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। *राज्य ब्यूरो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को बारां और झालावाड़ जिलों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सदन में घोषणा की कि परवन सिंचाई परियोजना की नई डीपीआर अब अपने अंतिम चरण में है। इस परियोजना के विस्तार से उन हजारों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जो अब तक इस नेटवर्क से बाहर थे।*

गरीब कल्याण के लिए नियमों में बदलाव : *प्रश्नकाल के दौरान विधायक राधेश्याम बैरवा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रावत ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारी साझा की।*

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन किसानों को भी मुआवजे के दायरे में शामिल किया है, जो चारागाह, वन या सरकारी भूमि पर बिना वैध दस्तावेजों के बसे हुए थे। मंत्री ने कहा, 'पिछली सरकार ने इन श्रेणियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन हमारी सरकार गरीब कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।'

मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने भूमि अवाप्ति के विरुद्ध 45 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर मंजूर की है। पात्र किसानों को चेक वितरित किए जा रहे हैं।

बजट 2025-26 में घोषित नई डीपीआर के पूरा होते ही निम्नलिखित क्षेत्रों के वंचित गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी:

बारां जिला : अटरू और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के छूटे हुए गांव।

झालावाड़ जिला : खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव।

स्थिति : अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डीपीआर का काम जल्द पूरा कर इसे धरातल पर उतारा जाए।

अटरू तहसील: मुआवजे की ताजा स्थिति

अटरू तहसील में दायीं मुख्य नहर के निर्माण से प्रभावित काश्तकारों का विवरण भी सदन में रखा गया।

कुल खातेदार : 685 किसानों की भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी।

लंबित प्रकरण : 36 मामले फिलहाल न्यायालय में हैं, जिनका भुगतान फैसले के बाद होगा।

विशेष अनुग्रह : 20 खातेदारों को विशेष अनुग्रह राशि के चेक देने की प्रक्रिया जारी है।

नए मामले: भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत छूटे हुए 86 अन्य खातेदारों पर भी कार्यवाही चल रही है।

नकली खाद-बीज माफिया पर सरकार का 'सर्जिकल स्ट्राइक'

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बोले-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

27 फैक्ट्रियां सीज, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, 169 डीलरों के लाइसेंस निरस्त

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राज्य ब्यूरो राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कृषि और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने 'नकली खाद-बीज माफिया' के खिलाफ सरकार के कड़े रुख को साफ कर दिया। विपक्ष द्वारा खाद की किल्लत और लाठीचार्ज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे सरकार मिलावटखोरों की कमर तोड़ रही है। डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने सदन को बताया कि प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। उन्होंने कार्रवाई का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि प्रदेशभर में 27 नकली खाद-बीज बनाने वाली फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। नकली खाद

के मामलों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं (जबकि पिछली सरकार में यह आंकड़ा मात्र 20 था)। अब तक 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 169 खाद डीलरों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

खाद की 'कमी' नहीं, 'डिमांड' में अचानक उछाल : सदन में खाद के लिए लगी कतारों पर जवाब देते हुए मंत्री ने तर्क दिया कि यह प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों का परिणाम है। उन्होंने कहा, 'इस बार मानसून लंबा चलने के कारण जमीन में नमी अधिक थी, जिससे बुवाई का रकबा अचानक बढ़ गया। मांग में आई इस आकस्मिक तेजी के बावजूद केंद्र से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए डॉ. किरोड़ी ने कहा कि पिछले शासनकाल में खाद के लिए किसानों पर लाठीचार्ज आम बात थी। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खाद वितरण को लेकर कहीं भी कोई अप्रिय घटना या लाठीचार्ज नहीं हुआ है।

विधानसभा का बजट सत्र 2026

सदन में गूंजा शिक्षकों की कमी का मुद्दा

मंत्री बोले-पिछली सरकार ने वोट बैंक के लिए स्कूल तो बढ़ाए, लेकिन शिक्षक नहीं दिए 72 हजार पद भरने का दावा

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राज्य ब्यूरो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों के मुद्दे पर सदन में भारी गहमागहमी देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने बिना तैयारी के स्कूलों को क्रमोन्नत कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

विधायक थावर चंद द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मदन दिलावर ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल राजनीति साधने के लिए स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन वहां शिक्षकों के नए पद सृजित नहीं किए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'वोट बैंक की खातिर स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन शिक्षक न होने से वहां की शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई।'

72 हजार भर्तियां और आगामी लक्ष्य : मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि वर्तमान भाजपा सरकार रिक्तियों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने महत्वपूर्ण आंकड़े पेश करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक करीब 72,000 पदों को भरने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। नई भर्ती प्रक्रियाएं गति पर हैं और जल्द ही स्कूलों को नए शिक्षक मिलेंगे। भर्तियों को नियमबद्ध और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

जवाब से असंतुष्ट उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सरकार को भाजपा के चुनावी 'संकल्प पत्र' की याद दिलाई। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने एक साल के भीतर सभी खाली पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में हजारों पद आज भी खाली हैं।

इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार एससी-एसटी और अन्य सभी वर्गों के आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि, मंत्री के इस जवाब पर विपक्षी सदस्यों ने असंतोष जताया, जिसके चलते सदन में काफी देर तक शोर-शराबे और नोक-झोंक की स्थिति बनी रही।

पीटीआई और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर स्पष्टीकरण

चर्चा के दौरान विधायक थावर चंद ने विशेष रूप से पीटीआई (शारीरिक शिक्षक) और कंप्यूटर अनुदेशक के खाली पदों का मामला उठाया। इस पर मंत्री दिलावर ने स्पष्ट किया कि विभाग नियमानुसार इन वर्गों की रिक्तियों को भी भरने की प्रक्रिया में है और किसी भी वर्ग के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।

सीकर यूआईटी का महाविस्तार : अब 88 गांवों की सरहद में बसेगा 'भविष्य का सीकर'

मास्टर प्लान-2047 का खाका तैयार

यूडीएच की अधिसूचना जारी : सीमा में शामिल हुए 38 नए गांव, संभाग और फंड को लेकर डोटासरा ने घेरा

सीकर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान की 'शिक्षानगरी' सीकर के नियोजित विकास के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगरीय विकास विभाग ने सीकर यूआइटी क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए 38 नए गांवों को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस विस्तार के साथ ही अब यूआइटी सीमा में गांवों की कुल संख्या 88 हो गई है।

अब 'विजन-2047' पर केंद्रित होगा मास्टर प्लान : प्रशासन ने शहर की बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मास्टर प्लान में बड़ा बदलाव किया है। पहले मास्टर प्लान साल 2041 को आधार मानकर बनाया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर साल 2047 की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाएगा। इससे पहले यूआइटी की सीमा में 50 राजस्व गांव जोड़े गए थे, अब 38 और गांवों के जुड़ने से शहर का भौगोलिक दायरा काफी बढ़ गया है।

आमजन को मिलने वाले 2 बड़े फायदे : सस्ता आशियाना: शहर के भीतरी इलाकों में बढ़ती कीमतों के बीच अब बाहरी गांव-ढाणियों में नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के रास्ते खुलेंगे, जिससे मध्यम वर्ग को किफायती घर मिल सकेंगे।

सुविधा क्षेत्र का विवाद खत्म : मास्टर प्लान में 'सुविधा क्षेत्र' के लिए जमीन की कमी को लेकर चल रहा विरोध अब शांत होने की उम्मीद है, क्योंकि नए गांवों के जुड़ने से सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी।

सीमा में शामिल प्रमुख गांव : अधिसूचना के अनुसार, अब पिपराली, सिंघासन, हर्ष (रैवासा), धाबाईपुरा, पीपली नगर, रसीदपुर, मैलासी, गोरीया, सुजावास और प्रेमसिंहपुरा जैसे प्रमुख गांव अब यूआइटी क्षेत्र का हिस्सा होंगे।

'कागजों पर संभाग, धरातल पर फंड नहीं' सरकार के इस फैसले पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने सीकर से संभाग का दर्जा छीनकर यहां के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि जब पुराने क्षेत्रों के विकास के लिए ही बजट उपलब्ध नहीं है, तो इतने बड़े नए क्षेत्र का विकास महज कागजी राजनीति बनकर रह जाएगा।

'सीकर यूआइटी का यह विस्तार शहर की सीमाओं को तो बढ़ाएगा, लेकिन असली चुनौती 2047 के विजन को धरातल पर उतारने और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड जुटाने की होगी।'

विधानसभा में प्रोटोकॉल की 'जंग'

स्पीकर और मुख्य सचेतक के बीच तीखी बहस, कांग्रेस का सदन वॉकआउट

जयपुर (विधानसभा संवाददाता)। राज्य ब्यूरो राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को एक दुर्लभ स्थिति देखने को मिली, जब सत्तापक्ष के ही मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) वासुदेव देवनानी के बीच प्रोटोकॉल को लेकर बहस छिड़ गई। विवाद की जड़ यह सवाल था कि क्या 'उप नेता प्रतिपक्ष' को 'नेता प्रतिपक्ष' के समान सवाल पूछने का अधिकार है?

गर्ग की आपत्ति: 'उप नेता को नहीं मिलता नेता वाला प्रोटोकॉल ' विवाद तब शुरू हुआ जब प्रश्नकाल के दौरान उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा बार-बार खड़े होकर मंत्रियों से स्पष्टीकरण मांग रहे थे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पर 'व्यवस्था का प्रश्न' उठाते हुए कड़ी आपत्ति जताई। गर्ग ने तर्क दिया कि रामकेश मीणा केवल 'उप नेता' हैं, उन्हें 'नेता प्रतिपक्ष' का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने पुराने सदन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे, तब राजेंद्र राठौड़ (तत्कालीन उप नेता) को भी उनकी अनुपस्थिति में सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी जाती थी।

स्पीकर का सख्त रुख: 'अनुमति मेरी, सवाल उनका'

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य सचेतक की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सदन की गरिमा और नियमों का हवाला देते हुए दो टूक कहा 'मैंने उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा को अनुमति दी है।

सदन नियमों और अध्यक्ष की अनुमति से चलता है। इसलिए वे प्रश्नकाल में किसी भी सवाल पर खड़े होकर मंत्री से जवाब मांग सकते हैं।'

एसटीपी के मुद्दे पर हंगामा और वॉकआउट : यह पूरा ड्रामा तब शुरू हुआ जब विधायक गोपीचंद मीणा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पीपीपी मॉडल को लेकर सवाल कर रहे थे। नगरीय विकास राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब के दौरान रामकेश मीणा ने हस्तक्षेप किया। स्पीकर की अनुमति के बावजूद मीणा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और तीखी बहस के बाद अंतत: कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विपक्ष के सदन छोड़कर जाने पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का तर्कपूर्ण जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का इस तरह का व्यवहार और सदन का बहिष्कार करना 'निंदनीय' है।

विधानसभा में घोषणा | **तबादलों की राह आसान करने के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी**

इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर के लिए बनेगी नई पॉलिसी मंत्री हीरालाल नागर

जयपुर (विसं)। *राजस्थान के ऊर्जा विभाग में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए विधानसभा से राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से 'इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर' (एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में तबादला) की मांग कर रहे बिजली कर्मियों के लिए सरकार नई नीति बनाने जा रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में घोषणा की कि इस जटिल मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा।*

विधानसभा में गूंजा तबादलों का दर्द : *प्रश्नकाल के दौरान विधायक भागचंद ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बिजली कर्मचारियों के स्थानांतरण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में कार्यरत हजारों कर्मचारी वर्षों से अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये कर्मचारी अपने गृह क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान नियमों की वजह से उनके तबादले नहीं हो पा रहे हैं।*

2010 के सुधारों ने बढ़ाई थी मुश्किलें : *विधायक के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में इंटर डिस्कॉम तबादलों का कोई सीधा कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने इसके पीछे के तकनीकी कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताया: वर्ष 2010 में राजस्थान पावर सेक्टर सुधार योजना के तहत अलग-अलग स्वतंत्र डिस्कॉम कंपनियां बनाई गई थीं।*

मेरिट और तैनाती: *नई भर्तियों में कर्मचारियों को उनकी मेरिट के आधार पर डिस्कॉम आवंटित किए गए। मेरिट में पीछे रहने वाले अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के बजाय जरूरत के अनुसार दूर-दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया।*

अब कमेटी तय करेगी भविष्य की राह : *मंत्री नागर ने स्वीकार किया कि कर्मचारी संघ लगातार मानवीय आधार पर राहत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'कर्मचारियों की परेशानियों और मानवीय पहलुओं को देखते हुए सरकार ने विधिक राय लेने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। यह कमेटी मौजूदा नियमों की समीक्षा करेगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही नई इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।'*

हजारों परिवारों में जगी उम्मीद : *सरकार के इस कदम से उन कर्मचारियों में खुशी की लहर है जो सालों से 'घर वापसी' की राह देख रहे हैं। यदि कमेटी की सिफारिशों के बाद नीति लागू होती है, तो यह बिजली विभाग के इतिहास में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार होगा।*

समाचार पत्र 'द पब्लिक हब' के समस्त संपादकीय एवं प्रकाशकीय विषयों पर स्वायत अधिकार सहित प्रकाशक, स्वामी व संपादक: दीपक गोस्वामी,
ए-101 यूनिक टावर, प्रताप नगर, जयपुर-302017, मो. 9828528666 मुद्रक: अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., जयपुर info@thepublichub.in, digital@thepublichub.in,
*पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार।

पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन ने पीडीकेएफ यूएसपीए पिंक को 5-3 से हराया

जयपुर (खेल संवाददाता)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रहे जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत शनिवार को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर यूएसपीए प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो कप 2026 का शानदार मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मैच में टीम पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन ने टीम पीडीकेएफ यूएसपीए पिंक को 5-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

इस अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी गौरवी कुमारी और यूएस पोलो एसोसिएशन विमेंसवियर की बिजनेस हेड स्वप्निता सिंह भी उपस्थित रहीं।

जयपुर में लेडीज पोलो कप 2026

टीम पीडीकेएफ यूएसपीए ग्रीन ने लांस वाटसन के नेतृत्व में बेहतरीन खेल दिखाया। वहीं टीम पीडीकेएफ यूएसपीए पिंक की कप्तानी जयपुर के हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने संभाली। विजेता टीम की ओर से कुमारी विजयश्री शक्तावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे जबकि डॉ. शिवांगी जय सिंह ने 2 गोल किए।

टीम की खिलाड़ी मिली शेठ ने भी प्रभावशाली खेल दिखाया। दूसरी ओर टीम पिंक की संजुला मान ने अकेले 3 गोल कर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। मैच में उर्वी सिंह और कुमारी लावण्या शेखावत ने भी भाग लिया।

यह प्रतिष्ठित मैच प्रिंसेस दीया कुमारी फाउंडेशन और यू.एस. पोलो एसोसिएशन के आधिकारिक ब्रांड यूएस पोलो एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। मुकाबले को देखने के लिए जयपुर के महिला संगठन, एनजीओ प्रतिनिधि, पोलो प्रेमी और शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस रोमांचक मुकाबले ने जयपुर पोलो सीजन 2026 को यादगार बना दिया और महिला पोलो खिलाड़ियों की प्रतिभा को नया मंच दिया।

खेल संक्षिप्त

ईशान किशन टी-20 आईसीसी बैटर रैंकिंग के टॉप 10 में

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ताजा टी-20 रैंकिंग जारी कर दी है। इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टॉप-10 बैटर्स में शामिल हो गए हैं। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्डकप में खेली गई 77 रनों की पारी का फायदा मिला। ईशान 17 पायदान चढ़कर बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लिस्ट में टॉप पर भारत के ही अभिषेक शर्मा हैं। गेंदबाजी में भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-1 टी-20 गेंदबाज बने हुए हैं। वहीं, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पाकिस्तान के सईम अयूब एक बार फिर नंबर-1 बन गए हैं। पाक के खिलाफ जीरो पर आउट होने वाले अभिषेक नंबर-1 भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ डक पर आउट होने के बाद भी ञ20ढ बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर काबिज हैं। श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैंडी में शानदार शतक जड़कर तीन स्थान की छलांग लगाई और तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इंडिया के तिलक वर्मा भी एक पायदान की छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

पंत चोट ठीक करने के लिए ले रहे थेरेपी का सहारा

नई दिल्ली (एजेंसी)। मार्च के आखिर में शुरू होने जा रहे आईपीएल 2026 से पहले भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं। बीते साल जुलाई महीने में भारत-इंग्लैंड टेस्ट सिरीज के दौरान ऋषभ पंत को पैर में गंभीर चोट लग गई थी। इस दौरान फिजियो के कंधे पर हाथ रखकर एक पैर के सहारे मैदान से बाहर का उनका वीडियो काफी चर्चा में रहा था। उससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में विकेटकीपिंग करते हुए उनकी बाएं हाथ की उंगली पर चोट लग गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, मैच के दौरान एक के बाद एक लगी इन्हीं चोटों और आईपीएल में बमुश्किल एक महीना बचे होने के कारण ऋषभ पंत ने हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी लेनी शुरू की है।

गंभीर को राजस्थान रॉयल्स से पार्टनर, मेंटर और सीईओ का मिला ऑफर

नई दिल्ली (एजेंसी)। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स से बड़ा प्रस्ताव मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के नए निवेशकों में से एक ने गंभीर को पार्टनर, मेंटर और सीईओ का ऑफर दिया है। साथ ही उन्हें 2 से 3 प्रतिशत इक्विटी स्टेक देने की भी पेशकश की गई है। बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी के अधिकतर मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी नए मालिकों को बेच रहे हैं और सौदा ट्रांसफर प्रक्रिया में है। हालांकि, गंभीर फिलहाल इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, ऐसे में वे यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ टीम इंडिया और किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ आधिकारिक भूमिका में नहीं रह सकता।

इंडो-इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन में भारत ने इंडोनेशिया को हराया

जयपुर (द पब्लिक हब)

राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के महासचिव शौकत अली मंसूरी के अनुसार बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ एशिया एवं इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में इंडो-इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज 2025-26 का आयोजन 13 से 19 फरवरी 2026 तक बाली, इंडोनेशिया में किया गया। इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया।

प्रतियोगिता में राजस्थान से महिला वर्ग में हर्षिता जूनवाल (जयपुर) एवं कुमकुम सोनी (चूरू) विजेता भारतीय महिला टीम का हिस्सा रहीं, जबकि हर्ष देतरवाल (चूरू) विजेता भारतीय पुरुष टीम के सदस्य रहे। राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के संरक्षक स्वामी बालमुकुंद आचार्य (विधायक, हवामहल विधानसभा), अध्यक्ष डॉ. राजपाल शर्मा, महासचिव शौकत अली मंसूरी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा सहित संघ के समस्त पदाधिकारियों ने विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने पर बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अल्काराज ने जीता कतर ओपन का खिताब

दोहा (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने एटीपी 500 इवेंट में एक और शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 50 मिनट में

वापसी कर रहे फ्रांसीसी आर्थर फिल्स को 6-2, 6-1 से हराकर कतर ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया। अल्काराज की कतर में यह जीत ऑस्ट्रेलियन ओपन में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनने के सिर्फ 20 दिन बाद आई है। एटीपी टूर ने अल्काराज के हवाले से कहा कि मैं इस साल और ज़्यादा की भूख लेकर आया था, जो 2025 में दोहा क्वार्टर-फाइनल में हार गए थे। मुझे लगता है कि हर टूर्नामेंट के बाद, हमें बस नए लक्ष्य तय करने होते हैं। मैं अपनी टीम के साथ कोर्ट पर और कोर्ट के बाहर जो कुछ भी किया है, उससे बहुत खुश और गर्वित हूं।

हरमनप्रीत बनी सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर

कैनबरा (एजेंसी)। भारत की महिला विश्व कप विजेता टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी-20 में खेलने के साथ ही सबसे अधिक मैच खेलने वाली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर बन गईं। हरमनप्रीत कौर ने गुरुवार को भारत के लिए सभी प्रारुपों में अपना 356वां मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। इसी के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की महान सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

मैच के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि हरमन भारत के लिए एक खास खिलाड़ी रही हैं। मैं उन्हें खेल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनने की बड़ी कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूं। कौर ने 2009 में

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने के बाद से छह टेस्ट मैच, 161 एकदिवसीय और 189 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं।

आईसीसी के अनुसार, वह भारत में महिला क्रिकेट क्रांति का एक बड़ा हिस्सा रही हैं और पिछले साल उन्होंने टीम को पहली बार विश्व चैंपियनशिप जिताई। बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाली कौर ने 140 एकदिवसीय पारियों में 37.05 की औसत से 4409 रन बनाए हैं, टेस्ट में 200 रन और टी-20 में 3820 रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के लिए आठ शतक और 38 अर्धशतक बनाए हैं।

भारत-पाक मैच की व्यूअरशिप ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को पीछे छोड़ा

मुंबई (एजेंसी)। जियो स्टार, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पार्टनर है, ने शुक्रवार को अनाउंस किया कि जियो हॉटस्टार पर भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने रीच और कंजम्प्शन में हिस्टोरिक माइलस्टोन सेट किए हैं। इस मैच ने 163 मिलियन की अभूतपूर्व डिजिटल रीच दर्ज की, जिससे यह टी20 फॉर्मेट में किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा मैच रीच बन गई, यहां तक कि इसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल की व्यूअरशिप को भी पीछे छोड़ दिया। मोबाइल पर, इस गेम ने किसी भी आईसीसी टी20 इवेंट के लीग स्टेज में सबसे ज़्यादा मैच रीच हासिल की और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पिछले इंडिया-पाकिस्तान मैच से 1.2 गुना ज़्यादा। सीटीवी पर, मैच की रीच 2024 एडिशन के इंडिया-पाकिस्तान मैच से 2.4 गुना ज़्यादा थी।

इस मैच को सभी स्क्रीन पर कुल

20 बिलियन मिनट तक देखा गया, जिससे फैंस की ज़बरदस्त एंगेजमेंट का पता चलता है। इससे पिछले एडिशन के मैच के मुकाबले कंजम्पशन में 42% की बढ़ोतरी हुई, जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 कर लिया।

लीनियर टीवी पर, जिस मैच का बेसब्री से इंतज़ार था, उसने उतना ही शानदार परफ़ॉर्मेंस दिया, टीवीआर में 71% की बढ़ोतरी हुई और यह 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला इंडिया-पाकिस्तान टी20 मैच बन गया।

शाकिब के खिलाफ कानूनी मामलों को तेजी से सुलझाना जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश के नवनियुक्त खेल मंत्री अमीनुल हक़ ने साफ़ किया है कि सरकार शाकिब अल हसन और मशरफ़े मुर्तजा के खिलाफ चल रहे क़ानूनी मामलों को तेजी से सुलझाना चाहती है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि आवामी लीग के पूर्व सांसद रहे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी जल्द से जल्द क्रिकेट के मैदान पर लौट सकें। बांग्लादेश की राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके अमीनुल हक़ उन 49 नए मंत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने मंगलवार को शपथ ली है। 12 फ़रवरी को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद सत्ता में बदलाव हुआ है। हक़ ने भरोसा दिलाया कि नई सरकार पूर्व कप्तानों के प्रति 'सहनशील और लचीला' रुख अपनाएगी।

2024 में अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों पर कई मुक़दमे दर्ज किए गए थे। मामले की गंभीरता और क्रिकेट में इनकी अहमियत को समझते हुए हक़ ने कहा, कि 'सरकार शाकिब और मशरफ़े से जुड़े मुक़दमों पर गौर करेगी। हमारा रवैया उनके प्रति नरम और लचीला रहेगा। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को सरकार अपने स्तर पर देखेगी। हम चाहते हैं कि शाकिब वापस बांग्लादेश लौटें। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मामले जल्द ही निपट जाएंगे ताकि उनकी वापसी का रास्ता साफ़ हो सके। हम शाकिब और मशरफ़े, दोनों को ही दोबारा बांग्लादेश क्रिकेट में सक्रिय देखना चाहते हैं।

दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप : पेगुला ने चौथा डब्ल्यूटीए 1000 टाइटल जीता

दुबई (एजेंसी)। जेसिका पेगुला के लगातार अच्छे प्रदर्शन का आखिरकार उन्हें इनाम मिला। लगातार छह बार बिना किसी टाइटल के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, उन्होंने शनिवार को एलिना स्वितोलिना को 1 घंटे 12 मिनट में 6-2, 6-4 से हराकर 2026 दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप जीती - यह उनका 10वां डब्ल्यूटीए टूर सिंगल्स क्राउन था। दो दिन पहले, पेगुला ने एक सेट और एक ब्रेक से उबरकर सेमीफाइनल में अमांडा अनिसिमोवा को हराया था, और पक्का इरादा किया था कि एक और शानदार हफ्ता हाथ से नहीं जाने देंगी। इस बार, उन्होंने इसे पूरा किया। उनका 10वां टाइटल डब्ल्यूटीए 1000 लेवल पर उनका चौथा टाइटल है, क्योंकि वह दुबई क्राउन जीतने वाली सिर्फ़ तीसरी अमेरिकन बन गईं, इससे पहले लिंडसे डेवनपोर्ट और तीन बार की चैंपियन वीनस विलियम्स भी दुबई क्राउन जीत चुकी हैं। ऐसा करके, उन्होंने 2023 डब्ल्यूटीए फाइनल के बाद, अपने करियर में सिर्फ दूसरी बार एक ही इवेंट में चार टॉप 20 जीत हासिल कीं। इस हफ़्ते की जीत में राउंड ऑफ़ 16 में इवा जोविक, क्वार्टर फाइनल में क्लारा टॉसन, सेमीफाइनल में अनिसिमोवा और आखिर में शनिवार के फाइनल में स्वितोलिना पर जीत शामिल है। स्वितोलिना के साथ नौ मुकाबलों में पेगुला की यह छठी जीत थी, लेकिन टॉप 10 में रैंक वाली दोनों खिलाड़ियों के साथ यह उनकी पहली जीत थी। शुरुआती गेम से ही यह साफ़ था कि मैच पेगुला के हाथ में था। उसने पहले दो पॉइंट गंवाए लेकिन अगले 10 पॉइंट जीते, पहले गेम में स्वितोलिना की सर्विस तोड़ी और दो गेम बाद फिर से सर्विस तोड़कर 3-0 की बढ़त बना ली। स्वितोलिना ने 3-1 के ब्रेक से कुछ देर के लिए राहत महसूस की, लेकिन पेगुला ने तुरंत 4-1 से वापसी की। यह एक जबरदस्त बढ़त थी जो काफी हद तक उसके फोरहैंड पर बनी थी, जिसका सबूत उसके लेटेस्ट ब्रेक को बुक करने के लिए फोरहैंड विनर्स से मिला।

भारत-ए टीम ने जीता महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब

बैंकॉक (एजेंसी)। तेजल हसबनीस (नाबाद 51), कप्तान राधा यादव (36) के बाद प्रेमा रावत (तीन विकेट) सहित अन्य गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ए महिला टीम ने रविवार को बांग्लादेश-ए टीम को 46 रनों से हराकर महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलादेश ए महिला टीम को साइमा ठाकोर ने तीसरे ओवर में इश्मा तंजीम (तीन) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। शमीमा सुल्ताना और सरमिन सुल्ताना की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। सातवें ओवर में प्रेमा रावत ने शमीमा सुल्ताना 15 गेंदों में (20) रन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। सरमिन सुल्ताना (18) को राधा यादव ने आउट किया।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे बंगलादेश के बल्लेबाज नियमित

अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। लता मंडल (एक), सादिया अख्तर (10), कप्तान फाहिमा खातून (14) और फरजाना ईस्मिन (छह) रन बनाकर आउट हुई। 18वें ओवर में तनुजा कंवर ने संजीदा अख्तर मेघला (पांच) को आउट कर भारत को आठवीं सफलता दिलाई। 20वें ओवर की पहली गेंद पर तनुजा कंवर ने शोरिफा खातून (नौ) को आउट कर बंगलादेश की टीम को 88 रन के स्कोर पर ढेर कर मुकाबला और खिताब 46 रनों से अपने नाम कर लिया। भारत ए महिला टीम के लिए प्रेमा रावत ने 12 रन देकर चार विकेट लिए। सोनिया मेंधिया और तनुजा कंवर को दो-दो विकेट मिले। राधा यादव, साइमा ठाकोर और मिन्नु मनी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां टॉस जीतकर भारत ए महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 44 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिये। दिनेश वृंदा 17 गेंदों में (19), नंदिनी कश्यप (आठ), मिन्नु मनी (शून्य) और अनुष्का शर्मा (आठ) रन बनाकर आउट हुई। ऐसे संकट के समय तेजल हसबनीस और कप्तान राधा यादव की जोड़ी ने पारी को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 69 रन जोड़े। 17वें ओवर में फाहिमा खातून ने राधा यादव को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। राधा यादव 30 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 36 रन बनाए। इसी ओवर की छठी गेंद पर

सेहत

ज्वाएंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के नए आयाम

टोटल ज्वाएंट रिप्लेसमेंट, (टीजेआर) सर्जरी अपंग बना देने वाले आर्थराइटिस बीमारी के इलाज के क्षेत्र में हुए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। टोटल ज्वाएंट रिप्लेसमेंट सर्जरी न सिर्फ अपंग बना देने वाले आर्थराइटिस के दर्द एवं कष्ट से मुक्ति दिलाती है, बल्कि जोड़ को एक नया जीवन देकर जिंदगी स्तर में आश्चर्यजनक रूप से सुधार लाती है। गाजियाबाद स्थित अटलांटा हॉस्पिटल के ओर्थपेडीक सर्जन डॉ अमित त्यागी बताते हैं की हाल के वर्षों में ज्वाएंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्रक्रिया में काफी कुछ क्रांतिकारी प्रगति हुई है। अभी तक आम तौर पर घुटने एवं हिप के जोड़ों का ही प्रतिस्थापन होता था, लेकिन अब कंधे, कोहनी, कलाई, अंगुली और टखने के जोड़ों को भी बदला जाने लगा है। धातु पर धातु सेरेमिक पर सेरेमिक जैसे कुछ नए पहलुओं के उभरने और क्रांस लिक्ड पोली एथिलीन के विकास की वजह से घिसने की दर में कमी और एक बेहतर निम्न घर्षण कृत्रिम जोड़ का निर्माण हुआ तथा जोड़ों की जीवन अवधि बड़ी। इस तरह इन जोड़ों को अपाहिज बना देने वाले आर्थराइटिस से पीड़ित कम उम्र के मरीजों में प्रत्यारोपण करना भी आसान हो गया है। गाजियाबाद स्थित अटलांटा हॉस्पिटल में टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कम पैसों में और आधुनिक तरीकों से सुविधा उपलब्ध है। जिसके चलते गाजियाबाद के आस पास के मरीजों में टोटल नी रिप्लेसमेट सर्जरी कम खर्च में हो रही है।और मरीज इसके उपयोग से स्वस्थ्य जीवन जी रहे हैं। डॉ त्यागी के अनुसार समकालीन टोटल नी रिप्लेसमेंट, (टी के आर) जो कि वर्तमान में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली ऑर्थोपेडिक शल्य चिकित्सा है। हालांकि टी के आर का लक्ष्य सरल है लेकिन उसे पूरा करने का साधन जटिल है और शल्य चिकित्सकों तथा अभियंताओं को मानवीय जोड़ों जैसे अंग तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। प्रक्रिया की सफलता न सिर्फ सर्जन और उसकी टीम की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है, बल्कि तैयार किए गए जोड़ की डिजाइन तथा संयंत्रों से भी उसका संबंध है। दरअसल एक वैज्ञानिक रूप से ठीक डिजाइन के साथ आसानी से इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों एवं तकनीकों का होना भी जरूरी है, जिसकी वजह से सटीकता तथा फिर से पहले जैसा होने की क्षमता आती है।आर्थोपेडिक सर्जरी में घुटने की शल्य चिकित्सा को लेकर एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसे यूनी.कमपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। जिस तरह से पिछले तीन दशकों के दौरान अच्छे परिणाम देकर दुनिया भर में अपने को साबित किया है। बदले जाने वाले अंगों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों तथा उनके डिजाइनों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शोध कार्य चल रहे हैं, ताकि वे जितना संभव हो सके उतनी सुगमता एवं सामान्य ढंग से काम कर सकें। आने वाले समय में और अधिक प्रतिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता एवं प्रोसथेसिस की कम दर टी जे आर के इलाज के बहुत ही लोकप्रिय विकल्प के रूप में स्थापित होगी।

क्यों होती है रक्त में आयरन की कमी

रक्त में आयरन बदलती जीवनशैली और आहार संबंधी गलत आदतों के कारण रक्त में आयरन की कमी या अनीमिया पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। वास्तव में अनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह कई बीमारियों का कारण होती है। समय रहते इस पर काबू पाकर सेहत संबंधी कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है।

आयरन की कमी के लक्षण

वैसे तो व्यक्ति के रक्त में आयरन की कमी है या नहीं, इसके लिए हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। जांच में निकलने पर मान लिया जाता है कि व्यक्ति रक्त में आयरन की कमी का शिकार है। लेकिन व्यक्ति के शरीर में आने वाले कुछ बदलाव भी इसके लक्षण हो सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में जानें।

बहुत अधिक थकान

शरीर में एनर्जी का संबंध ऑक्सीजन के संचार से होता है। अगर शरीर में रक्त में आहार के स्तर में कमी है तो ऑक्सीजन का संचार सही तरीके से नहीं होगा। जिससे आपको थकान महसूस होगी। अगर आपको भी हर समय थकान महसूस होती ह, तो हो सकता है कि आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो।

रक्त में आयरन की कमी

शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अन्य पोषक तत्वों के साथ-साथ खून की भी जरूरत होती है। खून ही शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती हैं। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आइए जाने रक्त में आयरन की कमी के कौन-कौन से संकेत है।

चेहरे और आंखों के रंग में बदलाव

त्वचा और आंखों के रंग से शरीर में खून की कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अनीमिक होने पर त्वचा का रंग पीला या सफेद दिखता है जो सामान्य गोरापन नहीं होता है। इसके अलावा, आंखों के ऊपरी भाग बिल्कुल सफेद दिखने से भी शरीर में खून की कमी का पता लगाया जा सकता है।

नाखूनों पर सफेद धब्बे

आपने देखा होगा कि कई बार हमारे नाखूनों पर छोटे-छोटे सफेद धब्बे हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि नाखूनों पर होने वाले यह सफेद धब्बे शरीर में खून की कमी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा नाखून का कमजोर होना भी रक्त की कमी का लक्षण होता है।

लगातार होने वाला सिरदर्द

कुछ लोगों में बिना किसी कारण के बहुत अधिक सिरदर्द की शिकायत रहती हैं। खून में आयरन की कमी से ऑक्सीजन मस्तिष्क तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे सिरदर्द की शिकायत बनी रहती है। अगर आपको भी बार-बार सिरदर्द होता है तो आपको अनीमिया हो सकता है।

सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी

खून की कमी होने पर कई बार सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत अधिक चलने व सीढ़ी चढ़ने जैसी गतिविधियों के दौरान सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। इसके अलावा सुबह उठते ही बहुत अधिक कमजोरी भी महससू होती है।

खून की कमी दूर करने के उपाय

अकेली रक्त में खून की कमी, कई बीमारियों की जड़ होती है। इसे जड़ को खत्म करने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी है। अनीमिया को दूर करने के लिए मांस, अंडा, मछली, किशमिश, सूखी खुबानी, हरी बीन्स, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे आयरन से परिपूर्ण आहार का सेवन महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भोजन से जुड़ी कुछ चीजों खून की कमी को दूर करने में मददगार होती है।

चुकंदर

चुकंदर आयरन का अच्छा स्त्रोत है। इसको रोज खाने में सलाद या सब्जी के रूप में शामिल करने से शरीर में खून की कमी नहीं होती।

हरी पत्तेदार सब्जी

पालक, ब्रोकोली, पत्तागोभी, गोभी, शलजम और शकरकंद जैसी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनके नियमित सेवन से वजन कम होने के साथ-साथ शरीर में खून में आयरन की मात्रा बढ़ती है। और पेट भी ठीक रहता है।

फल

तरबूज, सेब, अंगूर, किशमिश और अनार जैसे फल खाने से खून बढ़ता है। अनार खाना अनीमिया में काफी फायदा करता है। इसलिए रक्त में आयरन की कमी को दूर करने के लिए प्रतिदिन अनार का सेवन जरूर करें।

जानकारी

डिजिटल स्क्रीन से थकी आंखों के लिए वरदान हैं आयुर्वेद के ये सरल उपाय

'शीतोदक सेचन' और 'पानीतला स्पर्श'

लगातार घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठने से होने वाली आंखों की थकान और जलन अब एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। इससे निपटने के लिए आयुष मंत्रालय ने प्राचीन आयुर्वेद के दो विशेष उपायों 'शीतोदक सेचन' और 'पानीतला स्पर्श' के फायदों को साझा किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि ये उपाय न केवल आंखों को ठंडक देते हैं, बल्कि दृष्टि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी मददगार हैं।

1. शीतोदक सेचन : आंखों का प्राकृतिक कायाकल्प

इसका सरल अर्थ है आंखों को ठंडे और साफ पानी से धोना।

विधि : दिन में 3 से 4 बार साफ और शीतल जल से आँखों को धीरे-धीरे धोना चाहिए।

लाभ : यह आँखों की मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त संचार में सुधार करता है। नियमित उपयोग से डिजिटल स्क्रीन की थकान दूर होती है और रोशनी को मजबूती मिलती है।

2. पानीतला स्पर्श : नमी बनाए रखने का मंत्र

यह भोजन के बाद की एक प्राचीन भारतीय आदत है, जिसे अब विज्ञान भी प्रभावी मान रहा है।

विधि : भोजन के बाद हाथ धोते समय अपनी गीली हथेलियों को हल्के से अपनी बंद आँखों पर रखें।

लाभ : गीली हथेलियों का स्पर्श आँखों की नमी बरकरार रखता है और सूजन कम करता है। मंत्रालय के अनुसार, यह क्रिया भविष्य में मोतियाबिंद और 'रिफ्रैक्टिव एरर' जैसी समस्याओं से बचाव में सहायक है।

आंखों की सेहत के लिए मंत्रालय के अन्य सुझाव : मंत्रालय ने इन पारंपरिक उपायों के साथ आधुनिक जीवनशैली के लिए कुछ और टिप्स भी दिए हैं-

20-20-20 का नियम : हर 20 मिनट के स्क्रीन समय के बाद 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें।

त्रिफला जल : रात भर पानी में भीगे त्रिफला को छानकर उस पानी से सुबह आँखें धोना अत्यंत लाभकारी है।

आहार : विटामिन- ए और सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे आंवला, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में शामिल करें।

चेतावनी : ये उपाय सामान्य थकान और बचाव के लिए बताए गए हैं। यदि आँखों में अत्यधिक दर्द, लाली या दृष्टि कम होने जैसी समस्या महसूस हो, तो तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बनी उम्मीद की किरण

हैदराबाद (एजेंसी)। देश की प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही भारत के समग्र विकास में भी अहम योगदान दे रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि हितैषी नीतियों, तकनीक आधारित प्रक्रियाओं और समय पर दावों के निपटान का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय और आजीविका अधिक सुरक्षित हुई है। हालांकि, पीएमएफबीवाई का प्रभाव केवल आर्थिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। आर्थिक जोखिम को कम करके इस योजना ने किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक अपनाने, उत्पादन

बढ़ाने वाले संसाधनों में निवेश करने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

राजस्थान सरकार किसानों के हित में इस ऐतिहासिक फसल बीमा योजना को लागू कर राज्य की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला रही है। प्रशासन ने कृषि संकट कम करने, किसानों की कर्ज निर्भरता घटाने और खेती से जुड़े समुदायों में विश्वास बढ़ाने में सफलता हासिल की है। इसकी सफलता की कहानियां गांव-गांव में दिखाई दे रही हैं। अब किसान खेती को प्रकृति के भरोसे का जोखिम नहीं, बल्कि सरकार के सहयोग से सुरक्षित और टिकाऊ आजीविका के रूप में देख रहे हैं।

पीएमएफबीवाई के सफल क्रियान्वयन और किसानों को मिले लाभ पर बात करते हुए, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के चीफ रिस्क ऑफिसर कुमार सौरभ ने कहा, 'पीएमएफबीवाई पॉलिसी इनोवेशन और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की ताकत का एक सशक्त उदाहरण है।

हम सरकार के इस मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि योजना का दायरा और अधिक बढ़े, तकनीक का बेहतर उपयोग हो, और हर किसान चाहे वह किसी भी क्षेत्र या किसी भी फसल से जुड़ा हो, इस सुरक्षा का लाभ उठा सके।

बिना अनुमति देश छोड़कर जाऊंगा : अनिल अंबानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अनिल अंबानी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। यह हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच के बीच आया है। अंबानी ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया है कि वे ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये दोनों एजेंसियां अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही हैं।

अनिल अंबानी ने अपने हलफनामे में आधिकारिक तौर पर उस अंडरटेकिंग (वचन) को अपना लिया है, जो उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने 4 फरवरी को कोर्ट में पेश की थी। तब रोहतगी ने अदालत को मौखिक रूप से आश्वस्त किया था कि अंबानी देश छोड़कर नहीं जाएंगे। अब लिखित हलफनामा दाखिल होने के बाद यह कानूनी रूप से जरूरी हो गया है।

कोलगेट ने राहुल द्रविड़ को बनाया नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त

मुंबई (एजेंसी)। कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड ने दिग्गज क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कोलगेट टोटल का नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है। इस अवसर पर कोलगेट टोटल के ब्रांड एंबेसडर राहुल द्रविड़ ने कहा कि खेलों में प्रदर्शन की बात हो तो हर छोटी चीज मायने रखती है। मौखिक स्वास्थ्य भी ऐसा ही एक अहम पहलू है। इतना कि दुनिया भर की कई टीमें और हंसी फ्लिक जैसे कोच अब खिलाड़ियों के लिए डेंटल चेक-अप अनिवार्य करते हैं। मेरे लिए कोलगेट टोटल इसलिए खास है क्योंकि यह 8 डेंटल समस्याओं को रोकता है और आपको वह प्रोएक्टिव बढ़त देता है। कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के मार्केटिंग, ईवीपी, गुंजित जैन ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य हमेशा से खेल प्रदर्शन से जुड़ा रहा है।

सबसे पतला स्मार्टफोन पोवा कर्व-2 बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध

जयपुर (द पल्लिक हब)। आज के समय में पावर का मतलब है सहनशक्ति, निरंतरता और दिनभर की चुनौतियों के बावजूद कनेक्टेड रहना। काम के लंबे दिनों से लेकर अविश्वसनीय नेटवर्क तक, रोजमर्रा की जिंदगी बहुत कुछ मांगती है और अब, इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। पोवा कर्व 2 आधिकारिक तौर पर आज से बिक्री के लिए उपलब्ध है, जो वास्तविक दुनिया के संघर्ष के लिए डिजाइन किए गए स्लिम, कर्व्ड डिजाइन में अत्यधिक सहनशक्ति लेकर आया है। पोवा ने हमेशा स्मार्टफोन को पहचान का बैज माना है, जिसे खास तौर पर बोल्ड इंडियन स्पिरिट के लिए बनाया गया है। जहां ओरिजिनल पोवा कर्व ने अपने इनोवेटिवएस्थेटिक्स से अलग पहचान बनाई थी, वहीं पोवा कर्व 2 एक बड़ी छलांग है। स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग की शानदार सटीकता से प्रेरित होकर, यह 'कूल' फैक्टर को कुछ ज्यादा शार्प और सोफिस्टिकेटेड बनाता है, एक लॉन्चपैड-रेडी डिजाइन जो भीड़ में सबसे अलग दिखने के लिए बनाया गया है। तकनीक और डिज़ाइन के इस शक्तिशाली संयोजन को पूरे भारत में उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हुए, पोवा कर्व 2 एक आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है, यह स्मार्टफोन अभी फ्लिपकार्ट और देश भर के बड़े रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। खरीदार बड़े बैंक और एनबीएफसी पार्टनर से 3,000 रुपए तक का कैशबैक भी पा सकते हैं। पोवा कर्व 2 के मुख्य भाग में सेगमेंट-लीडिंग 8000 एमएएच की बैटरी है, जिसे बहुत ही शानदार ढंग से 7.42एमएम की स्लिमप्रोफाइल में पैक किया गया है और इसका वजन सिर्फ 195जी है।

टाटा ईवी ने पंच ईवी का नया अवतार किया लॉन्च

मुंबई (एजेंसी)। ईवी को मेनस्ट्रीम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, भारत में जीरो एमिशन पर्सनल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लीडिंग प्रोवाइडर, टाटा ईवी ने आज अपने पॉपुलर पंच ईवी का नया अवतार लॉन्च किया, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर ईवी अपनाने की नई लहर शुरू हो गई है। एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए डिजाइन की गई, नई पंच ईवीउन सभी चीजों को एक साथ लाता है जो कस्टमर न सिर्फ अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार में बल्कि अपनी पहली घरेलू कार में भी चाहते हैं।

यह ईवी ओनरशिप को रोकने वाली मुख्य रुकावटों अफोर्डेबिलिटी, रेंज कॉन्फिडेंस, चार्जिंग सुविधा और बैटरी एश्योरेंस को पूरी तरह से दूर करता है, जिससे बड़े पैमाने पर मेनस्ट्रीम ईवी अपनाने का पूरा समीकरण हल हो जाता है। सिर्फ 9.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, मुंबई) की आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च की गई, नई पंच ईवीएंट्री-लेवल स्मॉल-कार सेगमेंट में आईसीई ऑफरिंग के साथ ईवी ओनरशिप को लगभग ऑन-रोड कीमत के बराबर लाता है। टाटा ईवी बास का ऑप्शन भी दे रहा है, जो 9.69 लाख रुपए से शुरू होता है और बैटरी ईएमआई 2.6 /किमी है, जिससे कस्टमर के लिए एक दूसरा फाइनेंसिंग ऑप्शन मिलता है।

सैमसंग जल्द पेश करेगा सहज गैलेक्सी कैमरा अनुभव

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिन में खिंची गई फोटो को कुछ ही सेकंड में 'नाइट मोड' जैसा लुक देना हो, तस्वीर से गायब हिस्सों को वापस जोड़ना हो या कई तस्वीरों को मिलाकर एक शानदार इमेज बनानी हो-अब यह सब बेहद आसान होने वाला है। पहले इस तरह की एडिटिंग के लिए पेशेवर कौशल (प्रोफेशनल स्किल्स) या घंटों की मेहनत की जरूरत होती थी। लेकिन अब, आप अपने गैलेक्सी फोन पर बस कुछ शब्दों में अपनी जरूरत बताकर मिनटों में यह काम कर सकेंगे। यह गैलेक्सी कैमरा का अगला बड़ा विकास है-जो अब तक के सबसे ब्राइट गैलेक्सी कैमरा सिस्टम पर आधारित एक 'एंड-टू-एंड' अनुभव प्रदान करेगा। आज के दौर में मोबाइल कैमरे सिर्फ फोटो लेने तक सीमित नहीं रह गए हैं। लेटेस्ट गैलेक्सी एआई तकनीक अब फोटो खींचने, एडिट करने और शेयर करने की उन्नत क्षमताओं को एक ही 'सहज प्लेटफॉर्म' (इंट्यूटिव प्लेफॉर्म) पर लेकर आएगी। इसका परिणाम एक निर्बाध अनुभव और अधिक सुगम रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में सामने आएगा-जिससे यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने या जटिल टूल्स को समझने की जरूरत नहीं होगी। इससे कंटेंट बनाना पहले से कहीं अधिक तेज, सरल और स्वाभाविक हो जाएगा। इस बदलाव के मूल में यह सोच है कि-रचनात्मकता किसी तकनीकी जानकारी या अनुभव की मोहताज नहीं होनी चाहिए। शूटिंग से लेकर एडिटिंग तक, गैलेक्सी कैमरा ने मोबाइल फोटोग्राफी की संभावनाओं को पुनर्परिभाषित किया है। अब कोई भी यूजर आसानी से सिनेमैटिक वीडियो बना सकता है, रात के आसमान में तारों की गति को कैप्चर कर सकता है या कम रोशनी में भी बारीक विवरणों वाली तस्वीरें ले सकता है।

50 मीटर के 'डिजिटल खेल' से अफसरों ने ढाया नियमों का पहाड़

सज्जनगढ़ : इको-सेंसेटिव जोन में 300 करोड़ का 'अवैध' रिसॉर्ट

उदयपुर (विशेष संवाददाता)। झीलों की नगरी उदयपुर में भू-माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के कथित गठजोड़ ने सज्जनगढ़ अभयारण्य की सुरक्षा और पर्यावरण पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। उदयपुर के ग्राम कालारोही में नियमों को दरकिनार कर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से एक विशालकाय रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मीडिया में खबरें आने के बाद अब वन विभाग व उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी इस पूरे मामले को दबाने में लगे हैं।

50 मीटर की हेराफेरी से मिली 'हरी झंडी : नियमों के अनुसार, सज्जनगढ़ अभयारण्य के इको-सेंसेटिव ज़ोन (ESZ) की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक पक्का निर्माण प्रतिबंधित है। आरोप है कि इस प्रतिबंध से बचने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण (DA) और वन विभाग के अधिकारियों ने कागजी पैमाइश में बड़ा खेल किया है। गूगल मैप के साक्ष्य बताते हैं कि निर्माण स्थल प्रतिबंधित दायरे के भीतर है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में दूरी 1050 मीटर दिखाकर इसे तकनीकी रूप से सुरक्षित कर दिया। इसी 50 मीटर के हेरफेर के आधार पर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई।

यूडीए की कार्रवाई पर उठे सवाल मगरमच्छों पर मेहरबानी क्यों ?

उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाल ही में जनवरी 2026 में UDA ने बड़ी और मोरवानिया जैसे क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे के जरिए अवैध विला और होटलों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। ऐसे में सवाल उठता है कि सैटेलाइट और अत्याधुनिक तकनीक का दावा करने वाले विभाग को कालारोही का यह 4 लाख वर्ग फीट का अवैध निर्माण क्यों नजर नहीं आया? क्या स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली बिल्डर्स के खिलाफ हाथ डालने से कतरा रहा है? या फिर अवैध निर्माण का यह बड़ा खेल इन्हीं के संरक्षण में फल-फूल रहा है।

ईको-सेंसेटिव ज़ोन में 'अवैध' रिसॉर्ट मामला पीएमओ पहुंचा, ईडी से जांच की मांग

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं पर नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे एक विशालकाय रिसॉर्ट ने प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अब सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में न केवल अवैध निर्माण, बल्कि इसमें लगे भारी-भरकम काले धन की जाँच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराने की माँग की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उक्त प्रकरण की जांच के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग एवं जिला कलक्टर उदयपुर को पत्र लिखा गया है।

नियमों का खुला उल्लंघन

प्रोजेक्ट के निर्माण में स्वीकृतियों और धरातल की हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है। नियमानुसार इस प्रोजेक्ट को अधिकतम G+2 (दो मंजिल) की अनुमति मिल सकती थी, लेकिन वहाँ वर्तमान में G+4 (चार मंजिला) पक्का ढांचा खड़ा है। बिल्डर्स ने कथित तौर पर ऊपरी दो मंजिलों को 'अस्थायी ढांचा' बताकर फाइल पास कराई है। नियमों के तहत यहाँ केवल 96,000 स्क्वेयर फीट के निर्माण की किया जा सकता था, लेकिन मौके पर करीब 4 लाख स्क्वेयर फीट क्षेत्र को कवर कर लिया गया है।इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट में 80% जमीन को हरियाली के लिए छोड़ना था, लेकिन कंक्रीट का जाल बिछाकर इसे घटाकर मात्र 15% कर दिया गया है।

जयपुर के आसमान में 'हल्ला बोल'

सूर्य किरण और सारंग की जुगलबंदी ने जीता दिल

जल महल पर वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन

जयपुर (विशेष संवाददाता)। गुलाबी नगरी में जल महल की पाल पर भारतीय वायु सेना के शौर्य और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिला। वायु सेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने अपनी कलाबाजी से हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की और जांबाज पायलटों का उत्साहवर्धन किया।

सारंग टीम : हवा में लहराते पांच रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों के साथ सारंग टीम ने सटीकता का परिचय दिया। पांच हेलिकॉप्टरों ने मिलकर जटिल संरचनाएं बनाईं। उनके एरियल मूवमेंट्स और सामूहिक समन्वय ने वायु सेना के कड़े प्रशिक्षण की झलक पेश की। हेलिकॉप्टरों के बीच की सटीक दूरी और संतुलन को देखकर दर्शक दंग रह गए।

सूर्य किरण टीम

इसके बाद जेट विमानों ने आसमान में रंगों की बौछार कर दी। टीम ने लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान और फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसे कठिन करतब दिखाए। दर्शकों के बीच सबसे लोकप्रिय उनकी 'डीएनए' संरचना रही। हवा में लहराते तिरंगे रंगों ने पूरे वातावरण को देशभक्ति के उत्साह से भर दिया।

हमारे अपने 'आसमानी योद्धा': जयपुर के 3 लाल

इस प्रदर्शन की सबसे गौरवपूर्ण बात यह रही कि सूर्य किरण टीम के तीन पायलट हमारे अपने शहर जयपुर के ही निवासी हैं। विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह। जब इन पायलटों के नामों की घोषणा हुई, तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियों के साथ अपने स्थानीय नायकों का अभिनंदन किया। इस आयोजन ने वहां मौजूद एनसीसी कैडेट्स और स्कूली विद्यार्थियों में सेना के प्रति जबरदस्त जोश भर दिया। कई युवाओं ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार अनुभव बताया।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026

दिल्ली में चमका 'राजस्थान पवेलियन' मंत्री वैष्णव ने की नवाचारों की सराहना

शासन, स्वास्थ्य और कृषि में डिजिटल बदलाव पर विशेष ध्यान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत मंडपम, नई दिल्ली में 21 फरवरी को आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल विजन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'राजस्थान पवेलियन' का दौरा कर राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी कार्यों का अवलोकन किया। 20 स्टॉल्स में दिखा 'डिजिटल राजस्थान' सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार किए गए इस पवेलियन ने राजस्थान की तकनीकी क्षमताओं को बखूबी प्रदर्शित किया। पवेलियन में लगभग 20 स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे नवाचारों को दिखाया गया। यहां शासन में एआई का उपयोग, नागरिक-केंद्रित सेवाओं का डिजिटलीकरण, और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में एआई आधारित प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। यह आयोजन राजस्थान की डिजिटल गवर्नेंस में हुई प्रगति को देश के सामने रखने का एक बड़ा अवसर साबित हुआ।

भारत की एआई रणनीति के अनुरूप हैं राजस्थान के प्रयास

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे डिजिटल परिवर्तन की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के प्रयास भारत की समग्र एआई रणनीति के बिल्कुल अनुरूप हैं। मंत्री ने सराहा कि राजस्थान के नवाचार समावेशी, जिम्मेदार और सीधे नागरिक-केंद्रित विकास पर आधारित हैं। राज्य में एआई आधारित शासन को जिस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, वह डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती देता है।

क्या है राजस्थान का एआई विजन

समिट के दौरान बताया गया कि राजस्थान सरकार AI का उपयोग केवल तकनीक तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि इसे आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने का जरिया बना रही है। चाहे वो कृषि में फसलों की निगरानी हो या स्वास्थ्य सेवाओं में त्वरित निदान, राजस्थान AI को धरातल पर उतारने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

गौ संरक्षण के लिए 'ग्वाल' परंपरा की वापसी : मंत्री मदन दिलावर ने किया नई पहल का ऐलान

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गौ माता के संरक्षण और तस्करी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की घोषणा की है। मंत्री ने सदन में बताया कि प्रदेश के गांवों में अब फिर से 'ग्वाले' नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जो लावारिस और बेसहारा गायों की देखरेख करेंगे।

भामाशाहों के सहयोग से मिलेगा 10 हजार मानदेय

मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और जन-भागीदारी वाली मुहिम है।

वेतन: गांवों में नियुक्त होने वाले प्रत्येक ग्वाले को प्रतिमाह 10,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा।

फंडिंग: इस मानदेय का भुगतान सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दानदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से किया जाएगा।

निगरानी: पूरी व्यवस्था और ग्वालों के कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) की ओर से की जाएगी।

तस्करी और लावारिस छोड़ने की समस्या पर प्रहार

सदन को संबोधित करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि लोग गौ माता को उपयोग के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में तस्कर इन बेसहारा गायों को पकड़कर बूचड़खाने ले जाते हैं।

पुरानी परंपरा

पहले के समय में गांवों में गायों के लिए ग्वाले रखे जाने की समृद्ध परंपरा थी, जिसे अब फिर से जीवित किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि यह ग्वाला नियुक्ति की व्यवस्था पूरे राजस्थान के गांवों में लागू हो ताकि गौवंश सुरक्षित रह सके।

मंत्री ने अंत में दोहराया कि यह पहल पूरी तरह से समाज के सहयोग पर टिकी है और इसका उद्देश्य गौवंश की रक्षा के साथ-साथ ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करना है।

एक्सक्लूसिव रिपोर्ट : 237 करोड़ का जीएसएस 'महा-घोटाला'

33/11 केवी के अधूरे जीएसएस अब 'रिस्क एंड कॉस्ट' पर होंगे पूरे

जयपुर डिस्कॉम का दागी फर्म मैसर्स आर.सी. पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड पर बड़ा प्रहार

जयपुर (विशेष संवाददाता)। राजस्थान के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार के 'हाई-वोल्टेज' खेल का पर्दाफाश करते हुए जयपुर डिस्कॉम ने निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है।

बहुचर्चित 237 करोड़ रुपये के जीएसएस घोटाले की मुख्य आरोपी फर्म मैसर्स आर.सी. पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी की है। 10 फरवरी, 2026 को जारी आधिकारिक आदेश के बाद अब कंपनी के अधूरे छोड़े गए जीएसएस का कार्य 'रिस्क एण्ड कॉस्ट' के आधार पर पूरा कराया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार्य पूरा करने में आने वाला अतिरिक्त खर्च इसी दोषी कंपनी से वसूला जाएगा।

इन कार्यों को एआरसी या नई निविदा के माध्यम से तुरंत आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जनता को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। अधीक्षक अभियंता ने संबंधित सर्किल स्श्व को इस मामले को 'अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल' श्रेणी में रखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जांच दबाने का खेल : नेताओं और अफसरों की जुगलबंदी

- घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद उसे दो महीने तक सार्वजनिक नहीं होने दिया था।
- नेताओं का दबाव: दूदू, दौसा और सवाई माधोपुर के रसूखदार नेताओं ने जांच रोकने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया।
- भुगतान की साज़िश: रिपोर्ट को दबाए रखा गया ताकि कंपनी काम जारी रखकर भुगतान लेने की हकदार बनी रहे।

न्यायिक झटका हाईकोर्ट ने भी माना बड़ा भ्रष्टाचार

- कंपनी ने डिस्कॉम के टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गली।
- अदालत का फैसला जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने डिस्कॉम की प्रक्रिया को वैध मानते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी।
- कोर्ट ने माना कि इस प्रकरण में राजकोष को भारी नुकसान पहुँचने की आशंका है और योजना की वास्तविक लाभार्थी केवल कंपनी ही है।

चहेती फर्म के लिए बिछाया गया था 'रेड कारपेट'

- इस घोटाले की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम दौर में हुई, जहां 42 जीएसएस निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने की लूट की योजना बनाई थी।
- चहेती फर्म को काम दिलाने के लिए 'बूट मॉडल' जैसी विशेष शर्त जोड़ी गई, जो आरटीटीपी एक्ट का खुला उल्लंघन था। टेंडर का विभाजन प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए एक ही टेंडर को दो हिस्सों (20 और 22 जीएसएस) में बांट दिया गया था।
- 246% ऊंची दरें मिलीभगत का आलम यह था कि बिड मूल्यांकन कमेटी ने आंखें मूंद लीं और फर्म को बाजार दर से 246 प्रतिशत अधिक रेट पर काम सौंप दिया गया था।

मैसर्स आर.सी. पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड पर 3 साल का बैन और 'रिस्क एंड कॉस्ट' वसूली

10 फरवरी 2026 को जारी आदेश (क्रमांक 1455) के साथ ही फर्म मैसर्स आर.सी. पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड का 'वनवास' शुरू हो गया है। अधूरे पड़े 31 जीएसएस अब 'रिस्क एंड कॉस्ट' पर पूरे होंगे, यानी काम का सारा अतिरिक्त खर्च इसी दोषी कंपनी से वसूला जाएगा। अधीक्षक अभियंता ने इसे श्रेणी में रखते हुए सर्किल एसई को तुरंत नए सिरे से काम आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। ब्लैकलिस्टिंग फर्म को अगले 3 साल के लिए किसी भी सरकारी निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित कर दिया था।

लपेटे में आए दिग्गज: पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत, वित्त निदेशक एस.एन. माथुर, और मुख्य अभियंता आर.के. मीणा व अनिल गुप्ता को चार्जशीट।

अधिकारियों में अब बचाव का विवाद : तत्कालीन तकनीकी निदेशक और वर्तमान अजमेर डिस्कॉम एमडी के.पी. वर्मा को गवाह बनाने के नाम पर चार्जशीट से बाहर रखने पर सवाल उठ रहे हैं।

समाचार पत्र 'द पब्लिक हब' के समस्त संपादकीय एवं प्रकाशकीय विषयों पर स्वायत अधिकार सहित प्रकाशक, स्वामी व संपादक: दीपक गोस्वामी,
ए-101 यूनिक टावर, प्रताप नगर, जयपुर-302017, मो. 9828528666 मुद्रक: अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., जयपुर info@thepublichub.in, digital@thepublichub.in,
*पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेदार।